सोशल मीडिया से जुड़ें
NewsTransportVishesh
YouTube
Digital Edition

न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 1, अंक 97, नई दिल्ली, शुक्रवार, 03 फरवरी 2023, पेज 8

NEWS NTV TRANSPORT VISHESH
www.newstransportvishesh.com
सबसे तेज, सबसे पहले
आपको पहुंचाये
परिवहन क्षेत्र की सभी जानकारियां
09212122095
09811732095

03 पिछले ढाई महीनों कैदियों से जब्त हुए 348 फोन
05 Land Rover ने किया अपनी नई Range Rover Velar को
08 जनता के बीच जाने से पहले भाजपा सांसदों के साथ बैठक करेंगी वित्तमंत्री

आज का सुविचार

छोटी चीजों में बारे हमेशा वफादार रहिये क्योंकि इन्ही में आपकी शक्ति निहित होती है।

देश में अब वंदे भारत के साथ दौड़ती दिखेगी वंदे मेट्रो ट्रेन, हाइड्रोजन फ्यूल देगा रफ्तार

संजय बाटला

नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि शहरों में 50-60 किमी की दूरी तय करने को लेकर वंदे मेट्रो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। इस साल प्रोडक्शन और डिजाइन का काम हो जायेगा। अगले साल से इसे शुरू करने की योजना है। वंदे मेट्रो 125 से 130 किलोमीटर की रफ्तार के साथ दौड़ेगी...

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये अलॉट किए हैं। बजट पेश किए जाने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी भारतीय रेलवे को लेकर कुछ बड़े एलान किए। वंदे भारत ट्रेन की सफलता के बाद अब रेलवे 2024-25 तक वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि शहरों में 50-60 किमी की दूरी तय करने को लेकर वंदे मेट्रो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। इस साल प्रोडक्शन और डिजाइन का काम हो जायेगा। अगले साल से इसे शुरू करने

की योजना है। वंदे मेट्रो 125 से 130 किलोमीटर की रफ्तार के साथ दौड़ेगी। इसका डिजाइन मुंबई सब-अर्बन की तर्ज पर होगा। वंदे मेट्रो ट्रेन 1950 और 1960 में डिजाइन किए गए कई ट्रेनों को रिप्लेस करेगा। इंजन पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड होगा, जिसके कारण प्रदूषण जीरो होगा। इस ट्रेन में भी आधुनिक ब्रेक सिस्टम, रेड सिग्नल ब्रेक करने से रोकने के लिए कवच सेफ्टी सिस्टम, ऑटोमेटिक डोर, फायर सेंसर, जीपीएस, एलईडी स्क्रीन उपलब्ध होगी, जो यात्रियों को अगले स्टेशन के बारे में पूर्व सूचित करेगा। इस ट्रेन का किराया बेहद कम होगा, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भी सफर कर सकें।

अब इन जगह तैयार होगी वंदे भारत ट्रेन

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कई सालों से निवेश की जो कमी थी, इसके कारण रेलवे की जो क्षमता है वह हासिल नहीं हो पाती थी। रेलवे के उसी क्षमता को पूरा करने के लिए रेलवे के कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 2,41,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पैसेंजर्स के लिए सबसे जरूरी स्टेशन होता है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत देशभर के 1275 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण हो रहा है। इन स्टेशनों में नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-मुंबई जैसे बड़े स्टेशन के अलावा जोधपुर, जयपुर, गांधीनगर जैसे मीडियम रेलवे स्टेशन और तमाम छोटे रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का प्रोडक्शन बहुत तेजी से रैंप अप होगा। अभी तक वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण चेन्नई स्थित आईसीएफ में ही होता था, लेकिन अब इन प्रीमियम ट्रेनों का प्रोडक्शन सोनीपत, लातूर और रायबरेली में भी शुरू होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की तेज मैन्युफैक्चरिंग से देश का कोना-कोना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जुड़ जाएगा।

कई साल से टैक्स दबाए बैठे वाहन स्वामियों पर शिकंजा, आरसी जारी करने के आदेश

एनटीवी संवाददाता

देहरादून। आरटीओ (प्रवर्तन) तिवारी ने बताया कि हजारों की संख्या में ऐसे व्यावसायिक वाहन स्वामी हैं जो परिवहन विभाग का 50 करोड़ से अधिक का टैक्स दबाए बैठे हैं। वाहन स्वामियों से टैक्स वसूली को लेकर कई बार नोटिस जारी किए गए लेकिन टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में अधिकारियों को आरसी जारी करने के आदेश जारी किए गए है।

परिवहन विभाग का पिछले कई साल से टैक्स दबाए बैठे वाहन स्वामियों पर विभागीय अधिकारियों ने शिकंजा कस दिया है। परिवहन मुख्यालय के निर्देश पर संभागीय परिवहन अधिकारी ने ऐसे सभी बकायेदारों की आरसी जारी करने के आदेश जारी किए हैं। आरटीओ देहरादून के अलावा हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, विकासनगर, कोटद्वार समेत सभी परिवहन कार्यालयों में बकायेदारों की सूची चस्पा कर दी गई है। आरटीओ (प्रवर्तन) शैलेश तिवारी ने बताया कि हजारों की संख्या में ऐसे व्यावसायिक वाहन स्वामी हैं जो परिवहन विभाग का 50 करोड़ से अधिक का टैक्स दबाए बैठे हैं। वाहन स्वामियों से टैक्स वसूली को लेकर कई बार नोटिस जारी किए गए लेकिन टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में अधिकारियों को आरसी जारी करने के आदेश जारी किए गए है। सभी (एआरटीओ) को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने इलाकों में ऐसे तमाम वाहन स्वामियों को चिन्हित करने के साथ ही उसकी सूची राजस्व विभाग के अधिकारियों को मुहैया कराएं ताकि आरसी जारी करने के साथ ही वसूली की जा सके।

विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश

आरटीओ तिवारी ने बताया कि सभी एआरटीओ (प्रवर्तन) को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में राजस्व विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर पता लगाएं कि पूर्व में जो भी आरसी जारी की गई थी उसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

इनसाइड

ऑनलाइन दर्ज हुआ 861 सड़क दुर्घटनाओं का विवरण

गोंडा। सड़क सुरक्षा माह के अंतिम चरण में बुधवार को प्रशिक्षण का समापन हुआ। इसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आईरैड परियोजना के अंतर्गत सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों को गोल्डन ऑवर में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया कि 861 सड़क दुर्घटनाओं का विवरण ऑनलाइन अपलोड किया गया है। एनआईसी में आयोजित प्रशिक्षण की अध्यक्षता जिला सूचना विज्ञान अधिकारी गिरीश कुमार ने की। एनआईसी के जिला रोल आउट मैनेजर फैसल फत्ताह ने स्वास्थ्यकर्मियों को ऑनलाइन डेटा जैसे घायलों/मृतकों के नाम व पता, उपचार से संबंधित संपूर्ण विवरण, मेडिकल रिपोर्ट तथा पुलिस जांच से संबंधित रिपोर्ट आदि भरने के विषय में डेमो एप के माध्यम से तकनीकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एप के माध्यम से ही घायलों की मेडिकल रिपोर्ट, डिस्चार्ज रिपोर्ट, ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट रिपोर्ट, के साथ-साथ मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करके संबंधित थाने को ऑनलाइन सूचित करेंगे, जिससे पुलिस को अपनी आईडी पर उस एक्सीडेंट को लिंक करने के पश्चात सभी वांछित रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी।

50 नए हवाई अड्डे खुलेंगे, एनएचएआई को मिले 1.62 लाख करोड़

एनटीवी संवाददाता

नई दिल्ली। टाटा समूह के एअर इंडिया को खरीदने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए आवंटन में भारी कमी की गई है। उसे 3,113.36 करोड़ रुपये दिए गए।

सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूती प्रदान करने के लिए कई बड़े एलान किए हैं। इस दिशा में 50 नए हवाई अड्डे देश भर में खोले जाएंगे। टाटा समूह के एअर इंडिया को खरीदने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए आवंटन में भारी कमी की गई है। उसे 3,113.36 करोड़ रुपये दिए गए।

एनएचएआई को 1.62 लाख करोड़

राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र को 2.70 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का फंड बीते वित्त वर्ष की तुलना में 1.42 लाख करोड़ से बढ़ाकर 1.62 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।

लोकपाल को 92 करोड़ से ही करना पड़ा संतोष

भ्रष्टाचार विरोधी संस्था लोकपाल को अनुमान से कम 92 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। लोकपाल को पिछले वित्त वर्ष में 34 करोड़ रुपये दिए गए थे, इस वर्ष के लिए इसे संशोधित कर 197.50 करोड़ रुपये कर दिया गया था, लेकिन यह फंड लोकपाल को आवंटित नहीं किया गया।

सीबीआई को मिले 946 करोड़

केंद्रीय बजट में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 946 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो वित्त वर्ष 2023 की तुलना में 4.4 प्रतिशत अधिक है।

सीवीसी के हिस्से में आए 44.46 करोड़

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को पिछले बजट से एक करोड़ की मामूली वृद्धि देते हुए 44.46 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

तटीय नौ-परिवहन में पीपीपी मोड, जरूरत होने पर ही सरकारी फंडिंग मिलेगी। नागरिकों को परिवहन और माल ढुलाई के लिए जलमार्ग से साधन दिए

जाएंगे। ये परिवहन माध्यम न केवल सस्ते होंगे, बल्कि संचालन में ईंधन भी कम खर्च होगा।

रॉकेट व उपग्रह बनाने से लेकर पृथ्वी से चांद-सूरज तक नजर रखने के लिए 12,544 करोड़

पृथ्वी से लेकर चंद्रमा व सूर्य तक नजर रखने के लिए अंतरिक्ष विभाग अध्ययन मिशन भेज सके, यह ध्यान रखते हुए बजट 2023-24 में विभाग को 12,544 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। यह पिछले साल प्रस्तावित बजट 13700 करोड़ से तो 8.44 प्रतिशत कम हैं, लेकिन संशोधित अनुमान 10,530.04 से अधिक है। वहीं 2021-22 में 12,473.84 करोड़ रुपये का वास्तविक आवंटन हुआ था।

9,440.66 करोड़ रुपये खर्च होंगे अंतरिक्ष तकनीक पर

प्रमुख काम : रॉकेट व उपग्रह निर्माण, विकास व मिशन। यह राशि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसरो इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट, लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम्स सेंटर, इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स, यूआर राओ उपग्रह केंद्र, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स प्रणाली प्रयोगशाला, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसरो टेलिमेट्री पर भी खर्च होगी।

1558.95 करोड़ रुपये अंतरिक्ष एप्लीकेशन के लिए

प्रमुख काम : स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, विकास व शैक्षिक संचार केंद्र, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, पृथ्वी के पर्यवेक्षण मिशन और आपदा प्रबंधन से जुड़े कामों पर यह पैसा खर्च होगा।

ई-स्कूटर की ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर ठगी, पुलिस ने जारी किया अलर्ट

शिमला। प्रचलित इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्री बुकिंग के नाम पर ऑनलाइन ठगी के बाहरी राज्यों में बढ़ते मामलों के बाद हिमाचल पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। इसके साथ शिमला साइबर थाना पुलिस भी सतर्क हो गई है। साइबर ठग ई-स्कूटर बुक करने के नाम पर ग्राहकों को झांसे में लेकर अपना शिकार बना रहे हैं। ई-स्कूटर के नाम पर ठगी का यह खेल नया ट्रेंड बन गया है। हालांकि, हिमाचल में इस तरह का अभी तक कोई मामला नहीं आया है।

बावजूद, साइबर पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। साइबर पुलिस के मुताबिक शातिर ग्राहकों को होम डिलीवरी करके ई-स्कूटर बेचने के लिए फोन कॉल, ईमेल और सोशल मीडिया पर विज्ञापन के जरिये संपर्क कर रहे हैं। इसके साथ वेबसाइट पर ग्राहकों को ई-स्कूटर की फेंचाइजी खोलने पर फर्जी दस्तावेज देकर ठगी कर रहे हैं।

इसके अलावा ई-स्कूटर की बैटरी सेटअप, पॉवर स्टेशन के सेटअप के झांसे में लेकर फंसा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एएसपी साइबर भूपेंद्र नेगी ने बताया कि सोशल मीडिया एवं वेबसाइट के माध्यम से ई-स्कूटर बेचने के नाम पर मैसेज के जरिये ऑफर आता है तो उसकी सत्यता संबंधित थाना एवं पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन करके जांच सकते हैं। वहीं सहायक पुलिस अधीक्षक सुनील नेगी ने बताया कि इस तरह के मामलों से लोगों को बचाने के लिए पुलिस समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाती है लेकिन लोगों को खुद भी जागरूक होना होगा। लोग इस तरह के मामले आने पर तुरंत संबंधित थाने और साइबर पुलिस के पास संपर्क कर सकते हैं ताकि ठगी से बच सकें।

इस तरह लोगों को बनाते हैं शिकार

पुलिस के मुताबिक शातिर ओला इलेक्ट्रिक की एक फर्जी वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं। इसके जरिये वे ई-स्कूटर की जानकारी लेने के लिए वेबसाइट पर आने वाले लोगों से संपर्क करते हैं तथा उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। ग्राहक जैसे ही ओला ई-स्कूटी के बारे में जानकारी लेने के लिए गूगल पर सर्च करते हैं तो उन्हें वेबसाइट दिखती थी।

बसों की कमी से खाटू श्याम और अमृतसर की रोडवेज सेवा बंद

एनटीवी संवाददाता

जींद। डिपो में बसों की कमी का असर लंबे रूटों की सेवा पर पड़ रहा है। खाटू श्याम जाने वाली बसें 20 दिनों से बंद है। वहीं अमृतसर के लिए कोरोना काल के बाद से बस सेवा शुरू ही नहीं की गई। ऐसे में धार्मिक स्थानों पर जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। हालांकि डिपो प्रबंधन ने खाटू श्याम वाली बस बंद होने का कारण मंदिर में निर्माण कार्य चलने के चलते कपाट बंद होना बताया है जबकि बसों की कमी का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं ऋषिकेश, देहरादून जाने वाली बसें भी कोरोना काल से नहीं चलाई गईं। जींद और आसपास क्षेत्र से यात्री हरिद्वार सहित अन्य धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। बसों के बंद होने के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। फिलहाल जींद से

श्रीगंगानगर, मथुरा और सालासर तक की बसें जा रही हैं।

रोडवेज डिपो ने पिछले साल खाटू श्याम के लिए रोडवेज बस सेवा की थी। यह बस सुबह खाटू श्याम के लिए रवाना होती थी। इसमें जींद से काफी यात्री खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाते थे। रोडवेज डिपो को अच्छी आमदनी होती थी, लेकिन पिछले दिनों रोडवेज डिपो ने खाटू श्याम जाने वाली रोडवेज सेवा को बंद कर दी। अब दोबारा से इस रूट पर रोडवेज सेवा बहाल हो जाए तो यात्रियों को बेहतर सेवा मिल सकती है।

धार्मिक स्थानों पर बस शुरू करने की मांग शहरवासियों ने प्रदेश के आसपास के धार्मिक स्थानों के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू करने की मांग की है। उनकी मांग है कि जहां पहले रोडवेज बसें राजस्थान, पंजाब, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जाती थीं। वहां पर जाने के लिए जींद के लोगों को अच्छी परिवहन सेवा मिल जाती थी, लेकिन धार्मिक स्थानों पर जाने के लिए अब परिवहन सेवा नहीं मिल रही है।

खाटू श्याम मंदिर में निर्माण कार्य के चलते कपाट बंद है। इसको लेकर वहां श्रद्धालुओं की भीड़ कम हो गई थी जिससे बस की रिसिप्ट भी कम हो गई थी। जैसे ही मंदिर के कपाट खुलेंगे। रोडवेज सेवा बहाल कर दी जाएगी।-कर्मबीर तोमर, डीआई, रोडवेज डिपो जींद।

फरीदाबाद स्थित ऐस कंपनी ने इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में हो रहे बौमा कानेक्सपो में लांच किया

देश की पहली इलेक्ट्रिक क्रेन, सिंगल चार्ज में 10 घंटे करेगी काम; डीजल से होने वाले प्रदूषण से मिलेगी राहत

एनटीवी संवाददाता

इसकी कीमत करीब 50 लाख रुपये है जो डीजल के मुकाबले 15-18 लाख रुपये अधिक है। लेकिन डीजल की खपत न होने से जो अधिक पैसा क्रेन को खरीदने में लगेगा इसकी भरपाई डेढ़ से दो वर्ष में हो जाएगी।

ग्रेटर नोएडा। निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले भारी वाहनों में डीजल का ही बोलबाला रहा है, लेकिन अब निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली क्रेन इलेक्ट्रिक से भी संचालित होगी। फरीदाबाद स्थित ऐस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक मोबाइल क्रेन (ऐस एफ150-ईवी) को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में हो रहे बौमा कानेक्सपो में लांच किया है।

पूरी तरह से स्वदेश निर्मित इस क्रेन को चार्ज करने में आठ घंटे लगेंगे। एक बार पूरी तरह से चार्ज होने पर यह क्रेन 10-12 घंटे काम कर सकती है। 15 हजार किलोग्राम का भार उठाने की

इसकी क्षमता है। डीजल से चलने वाली क्रेन के जितनी ही इसकी क्षमता भी है।

प्रतिघंटे पांच लीटर की खपत करती है डीजल क्रेन

कंपनी के कार्यकारी निदेशक सौरभ अग्रवाल ने बताया कि इसी क्षमता की डीजल क्रेन एक घंटे में पांच लीटर डीजल की खपत करती है। इलेक्ट्रिक क्रेन से डीजल का खर्च तो बचेगा ही साथ ही जो हानिकारक पार्टिकल्स व गैस डीजल इंजन से निकलते हैं उससे भी बचाव होगा। पर्यावरण संरक्षण में इसका अहम योगदान रहेगा।

नहीं लगाना पड़ेगा अलग से चार्जिंग सेटअप

सौरभ अग्रवाल ने बताया कि घरों में आमतौर पर लगने वाले 16 एम्पियर के स्विच में भी इसके चार्जिंग प्वाइंट को लगाया जा सकता है। इसके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में चार्जिंग प्वाइंट पर होना वाला खर्च भी बचेगा।

इसकी कीमत करीब 50 लाख रुपये है, जो डीजल के मुकाबले 15-18 लाख रुपये अधिक है। लेकिन डीजल की खपत न होने से जो अधिक पैसा क्रेन को खरीदने में लगेगा इसकी भरपाई डेढ़ से दो वर्ष में हो जाएगी। अमेरिका, यूरोप और जापान की कंपनियों ने इलेक्ट्रिक से संचालित होने वाली इस क्रेन में रुचि दिखाई है।

बैट्री डिस्चार्ज का क्षमता पर नहीं पड़ेगा असर

क्रेन की बैट्री एक बार चार्ज होने पर 10 घंटे तक चलेगी। कंपनी अधिकारी ने बताया कि धीरे-धीरे बैट्री डिस्चार्ज होती जाएगी, लेकिन क्रेन पूरी क्षमता के साथ काम करती रहेगी। पूरी तरह से बैट्री डिस्चार्ज होने के करीब आधे घंटे पहले इसकी सूचना चालक को मिल जाएगी।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड
कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट
कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

इनसाइड

महिलाएं हर दिन करें ये 3 योगासन, बिना जिम के मिलेगा स्लिम-ट्रिम लुक

एक्सरसाइज या योग करना सेहत के लिए फायदेमंद है. नियमित योग और एक्सरसाइज करने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है. इससे कई बीमारियों से निजात भी मिलती है. बिजी रहने की वजह से या घर से बाहर न जाने की आदत के चलते कई बार महिलाओं के लिए जिम या योग केंद्र जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है. कई बार महिलाएं चाहते हुए भी जिम नहीं जा पाती हैं और अपनी सेहत के साथ समझौता कर लेती हैं. हालांकि अगर आप चाहें तो घर में रहकर भी कुछ खास योगासन की मदद ले सकती हैं. जो आपको स्वस्थ रखने में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं.

यूपी के लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट की क्लीनिकल योग इंस्ट्रक्टर डॉ. वंदना अवस्थी से उन योगासनों के बारे में जानते हैं, जो आपको स्वस्थ रखने के साथ कई बीमारियों से राहत देने में मदद करेंगे. वैसे तो कोई भी आसन सुबह के समय करना बेहतर होता है लेकिन समय न मिलने पर जब भी करें तो खाना खाने के बाद कम से कम दो घंटे का गैप जरूर रखें. इतना ही नहीं इन योगासनों को करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

चक्की चलनासन

इस योगासन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर योगा मैट बिछाकर बैठ जायें. अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला कर मैक्सिमम गैप बनाएं. इस दौरान रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे. अब हाथों को जमीन पर एकदम सामने की ओर सीधा रखकर उंगलियों को आपस में फंसा लें. फिर अपने हाथों को क्लॉक वाइज यानी दायीं से बायीं तरह गोल-गोल उसी तरह से घुमायें जैसे चक्की चलाई जाती है. इसके बाद विपरीत दिशा में यही प्रक्रिया दोहराएं. इस योगासन को शुरू में एक-दो मिनट करें फिर धीरे-धीरे समय को बढ़ाएं. इस योगासन से पीसीओडी की दिक्कत में राहत मिलती है. जिससे अनियमित मासिक धर्म धीरे-धीरे नियमित होने लगता है साथ ही दर्द और ऐंठन से भी राहत मिलती है. इतना ही नहीं ये मेंटल स्ट्रेस को कम करने और मोटापे से निजात दिलाने में भी मदद करता है.

तितली आसन

तितली आसन करने के लिए योगा मैट पर सूर्य की ओर मुख कर के आराम की मुद्रा में बैठें. फिर अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला कर इस तरह से मोड़ें जिससे दोनों पैरों के तलवे आपस में मिल जायें. अब दोनों हाथों से पैर के तलवों को अच्छी तरह से पकड़ लें.अब तितली की तरह अपने पैरों को हिलाएं. इस आसन को भी शुरू में एक-दो मिनट करें फिर अपनी कैपिसिटी के अनुसार धीरे-धीरे इसका समय बढ़ाएं. तितली आसन करने से भी पीसीओडी की दिक्कत से राहत मिलती है. साथ ही पीठ का दर्द और मसल्स स्ट्रेस भी दूर होता है. इतना ही नहीं इस आसन को तीन महीने की गर्भावस्था के बाद भी किया जा सकता है. ये आसन डिलीवरी को आसान बनाने में भी मदद करता है. नियमित रूप से तितली आसन करने से ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है.

दंडासन

दंडासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर बैठ जायें और पैरों को सामने की ओर फैला कर आपस में मिला लें. फिर दोनों हाथों को कंधों के बराबर अपनी जांघों के पास सीधा जमीन पर रखें.इस बीच रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें. अब दोनों पैरों के पंजो को अपनी ओर खींचें, कुछ सेकेंड रोक कर रखें फिर ढीला छोड़ दें. इस प्रक्रिया को दस से पंद्रह बार अपने सामर्थ्य के अनुसार दोहराएं. इस आसन को किसी भी आयु और अवस्था की महिलाएं आसानी से कर सकती हैं. दंडासन करने से कंधों में खिंचाव की दिक्कत कम होती है. रीढ़ की हड्डी लचीली और मजबूत होती है, मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और पाचन शक्ति बढ़ती है।

वर्किंग वूमन ऑफिस जाने से पहले बैग में जरूर रखें 7 चीजें, कभी भी पड़ सकती है जरूरत, कई काम होंगे आसान

घर से बाहर निकलते समय महिलाएं हैंड बैग कैरी करना नहीं भूलती हैं. खासकर नौकरी करने वाली महिलाएं ऑफिस जाते समय ज्यादातर चीजें हैंड बैग में ही रखती हैं. हालांकि अगर आप वर्किंग वूमन (Working women) हैं तो आपको कुछ खास चीजें अपने हैंड बैग में जरूर कैरी करनी चाहिए. ऑफिस में न सिर्फ आपको इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है बल्कि इनसे आपके बहुत से काम भी आसान बन सकते हैं. आमतौर पर देखा जाता है कि ऑफिस गोइंग वूमन ज्यादातर अपने पर्स में मेकअप का सामान और ऑफिस की फाइल्स कैरी करती हैं. हालांकि हैंड बैग में इन 7 जरूरी चीजों को शामिल करके आप रोजमर्रा की कई परेशानियों से चुटकियों में निपट सकती हैं. तो आइए जानते हैं वर्किंग वूमन के लिए हैंड बैग अपडेट करने के कुछ खास टिप्स के बारे में.

फोन का चार्जर रखे: कई बार काम में बिजी होने के कारण महिलाएं फोन चार्ज करना भूल जाती हैं. वहीं आपकी सेफ्टी के लिए भी फोन का चार्ज होना बेहद जरूरी होता है. ऐसे में आपको ऑफिस में दूसरों से चार्जर मांगना पड़ सकता है. इसलिए हैंड बैग में चार्जर कैरी करना न भूलें.

पर्स में रखें पेन-पेपर: वर्किंग वूमन के हैंड बैग में पेन और पेपर होना भी जरूरी होता है. इससे ऑफिस वर्क के दौरान आपको पेन और पेपर के लिए दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है. साथ ही ऑफिस के अलावा भी पेन और पेपर कई जगहों पर यूजफुल साबित होता है.

कैश रखना न भूलें: आजकल की डिजिटल लाइफस्टाइल में ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते हैं. हालांकि वर्किंग वूमन को हैंड बैग में कुछ खुले पैसे भी रख लेने चाहिए. इससे आपको ट्रैवलिंग और बाकी जरूरत के समय दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

हैंड बैग में रखें हैंकी या पेपर नैपकिन: ऑफिस जाते समय हैंड बैग में हैंकी या टिशु पेपर भी जरूर रख लें. ऐसे में मेकअप साफ करने से लेकर गंदे हाथों को पोछने के लिए आप रुमाल या टिशू पेपर का इस्तेमाल कर सकती हैं.

ईयर फोन भी जरूर रखें: कई बार महिलाएं अपना ईयर फोन घर पर रख देती हैं. हालांकि ऑफिस वर्क के दौरान आपको जरूरी वॉइस नोट या वीडियो देखना पड़ सकता है. इसलिए बैग में ईयरफोन या हेडफोन कैरी करना न भूलें.

सैनिटरी पैड्स कैरी करें: कई बार महिलाएं अपने पीरियड्स की डेट को मिस कर देती हैं. ऐसे में अचानक पीरियड्स आने पर आपको काफी परेशानी उठानी पड़ जाती है. इसलिए वर्किंग वूमन को हैंड बैग में सैनिटरी पैड्स जरूर रखने चाहिए. इससे आप पीरियड्स को लेकर बेफिक्र रह सकती हैं.

सेफ्टी पिन भी रखें: घर से बाहर रहने के दौरान सेफ्टी पिन से आप कई बिगड़े काम बना सकती हैं. ऐसे में ड्रेस फटने से लेकर बैग की चेन खराब होने या अन्य किसी काम में सेफ्टी पिन बेहद मददगार साबित हो सकती है. इसलिए वर्किंग वूमन को बैग में सेफ्टी पिन भी जरूर रखनी चाहिए.

पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हो जाती है इन विटामिंस की कमी, प्रेग नेंसी में दिक कत का ये भी है कारण

पुरुषों की तुलना में अक सर ये देखा जाता है कि महिलाओं में आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन डी, विटामिन बी12 जैसे जरूरी तत वों की कमी हो जाती है. अगर महिलाएं खुद की सेहत का ख याल रखें तो प्रेगनेंसी या मेनोपॉज के दौरान समस याओं से बच सकती है. आइए जानते हैं कि किन विटामिन की कमी महिलाओं में अक सर देखने को मिलती है. अक सर महिलाओं की ये शिकायत रहती है कि रात भर सोने के बावजूद थकान महसूस करती हैं या उन हें हर वक त कमजोरी का अनुभव होता है. इन समस याओं को वे लंबे समय तक नजरअंदाज करती जाती हैं जो आगे चलकर बड़ी बीमारियों की वजह बन जाता है. अगर महिलाएं अपनी सेहत का ध यान रखें और शरीर में विटामिन स और मिनरल स की कमी की आपूर्ति के लिए हेल दी डाइट लें तो जीवन भर हेल दी जीवन जी सकती हैं.

वुमनहेल थ के मुताबिक, दरअसल, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर को विटामिन और खनिजों की आवश्यकता पड़ती है. हर विटामिन और मिनरल स के अपने अलग फायदे हैं जो शरीर के अलग अलग कामों को पूरा करने में मदद करते हैं. लेकिन कई वजहों से महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कुछ खास तरह के विटामिन और खनिजों की कमी पाई जाती है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को किन विटामिन की कमी हो जाती है और वे किस तरह इन हें पूरा कर सकती हैं.

फॉलिक एसिड या विटामिन बी9

फॉलिक एसिड शरीर में ब लड सेल स बनाने और डीएनए क्रिएट करने का काम करता है. यह भ्रूण के बेहतर विकास के लिए बहुत जरूरी है. इसकी कमी से प्रीमेच योर बर्थ या जन म के समय कम वजन होने का खतरा हो सकता है. ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं को रोजाना 400 से 800 एमसीजी फॉलिक एसिड डायटरी सेप लीमेंट के रूप में दिया जाता है. इसकी आपूर्ति के लिए आप हरी पत तेदार सब्जियां, फल, अनाज, नट्स, चिकन आदि का नियमित सेवन करें.

विटामिन बी12

विटामिन बी12 ब लड सेल स और ब्रेन न यूरॉन बनाने का काम करता है. यह भी प्रेगनेंसी में जरूरी होता है. इसके अलावा जो महिलाएं शाकाहारी हैं और जिनकी उम्र 50 से अधिक है उन हें विटामिन बी12 की कमी हो सकती है. इसके लिए आप मिल क, अंडा, चीज, चिकन, लीवर आदि डाइट में शामिल कर सकती हैं.

विटामिन डी

शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी जरूरी होता है. यह इम यूनिटी को भी बढ़ाता है. जबकि सूरज की रौशनी से स्किन का डायरेक ट संपर्क ना होने की वजह से महिलाओं में विटामिन डी की काफी कमी पाई जाती है. इसके लिए आप सेप लीमेंट का इस तेमाल कर सकती हैं.

कैल्शियम

लड़कियों को ग्रोइंग एज में जहां 1300 एमजी कैल्शियम की जरूरत होती है, वहीं मेनोपॉज के बाद 1200 एमजी कैल्शियम की जरूरत होती है. लेकिन अधिकतर मामलों में महिलाओं में इसकी कमी पूरी नहीं हो पाती. इसके लिए आप कैल्शियम रिच फूड का सेवन करें और सेप लीमेंट का सेवन करें.

आयरन

महिलाओं में आयरन की कमी की समस या भी काफी आम है. जिस वजह से उनके शरीर में ब लड सेल स की कमी हो जाती है और ऑक सीजन सप लाई सही तरीके से ना हो पाने के कारण कमजोरी, चक कर आना जैसी समस या होने लगती है. ऐसे में आप आयरन रिच चीजों को डाइट में शामिल करें.

विंटर में इन चीजों को कहें न , सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर

सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए ज्यादातर महिलाएं हेल्दी डाइट चार्ट फॉलो करती हैं. डाइटिशियन भी सर्दियों में घी, ड्राई फ्रूट्स, गुड़, अदरक, शकरकंद, गाजर, सरसों का साग और केसर जैसी चीजों को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं. सर्दियों के दौरान ज्यादातर महिलाएं आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी ठंडी चीजें भी खाना पसंद करती हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि सर्दियों में ठंडी चीजें खाने से सेहत को कई नुकसान हो सकते हैं. आइए आपको बताते हैं सर्दी में ठंडी चीजों का सेवन करने के कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में.

पेट की प्रॉब्लम्स

हेल्थशॉट्स के अनुसार सर्दियों में ठंडा खाना खाने से आपको पेट से जुड़ी कई समस्याएं देखने को मिल सकती हैं. मसलन सर्दियों में ठंडी चीजों का सेवन करने से आपको पेट में सूजन, ऐंठन, पेट फूलना, थकान, बॉडी में शॉक महसूस होना और पाचन तंत्र वीक होने जैसी परेशानियां हो सकती हैं.

शरीर का तापमान कम होना

सर्दी के मौसम में बाहर का तापमान सामान्य से काफी नीचे चला जाता है. ऐसे में ठंडी चीजें खाने से आपकी बॉडी का टेंप्रेचर भी कम होने लगता है. जिससे ब्लड सर्कुलेशन पर बुरा असर पड़ता है और आपका खून जम भी सकता है.

गले में हो सकता है इंफेक्शन

जानकारों के अनुसार सर्दियों में ठंडा खाना खाने से आपको गले में थ्रोट इंफेक्शन हो सकता है. खासकर सर्दी के मौसम में कोल्ड कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडे जूस पीने से आपको गले में खुजली, जलन और इरिटेशन होने लगती है. ऐसे में गले का खास ख्याल रखने के लिए आप गर्म दूध, सूप, नट्स, मसाले और हर्ब्स का सेवन कर सकते हैं.

जुकाम होने का खतरा

सर्दी के मौसम में बॉडी काफी सेंसटिव हो जाती है. ऐसे में ठंडी चीजों का सेवन करना बीमारी को बुलावा देने जैसा होता है. बता दें कि सर्दियों के दौरान ठंडी चीजें खाने से आप खांसी, जुकाम, बुखार और सीजनल फ्लू जैसी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं.

पाचन पर पड़ेगा बुरा असर

सर्दियों में ठंडी चीजों का सेवन पाचन तंत्र को भी खासा प्रभावित करता है. दरअसल ठंडी चीजें काफी हैवी होती है. जिसे पचाने में आपको काफी दिक्कत आ सकती है. वहीं पाचन तंत्र कमजोर होने से आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो सकता है.

महिलाएं 40 साल के बाद जरूर करें इन चीजों का सेवन, जोड़ों में नहीं होगा दर्द, हेल्दी रहने में मिलेगी मदद

बढ़ती उम्र के साथ सेहत का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है. खासकर महिलाओं में उम्र बढ़ने के साथ उनका एनर्जी लेवल भी कम होने लगता है. वहीं प्रॉपर हेल्थ केयर रूटीन फॉलो न करने पर महिलाएं कई गंभीर बीमारियों का भी शिकार हो सकती हैं. ऐसे में अगर आपकी उम्र 40 साल से अधिक है तो 5 सप्लीमेंट (Necessary supplements) को डाइट में शामिल करके आप हमेशा हेल्दी रह सकती हैं.

40 से अधिक उम्र वाली ज्यादातर महिलाओं के शरीर में पोषण की कमी देखने को मिलती है. जिसके चलते महिलाओं की मसल्स कमजोर होने लगती है. ऐसे में महिलाओं को कमर दर्द, घुटनों में दर्द या हड्डियों में दर्द की परेशानियां उठानी पड़ती हैं. हालांकि ओनली माई हेल्थ के अनुसार कुछ सप्लीमेंट्स को डाइट का हिस्सा बनाकर आप न सिर्फ बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी कर सकती हैं बल्कि 40 के बाद भी खुद को फिट और हेल्दी रख सकती हैं.

विटामिन बी 12

विटामिन बी 12 खाने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है और ब्रेन भी अच्छी तरह से फंक्शन करता है. इसके अलावा पेट की एसिडिटी से निजात पाने के लिए भी विटामिन बी 12 युक्त चीजें खाना बेस्ट होता है. ऐसे में महिलाएं अंडा, मछली और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी पूरी कर सकती हैं.

कैल्शियम

40 साल के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी पर हड्डियां कमजोर होने लगती हैं. ऐसे में दूध और पनीर जैसी कैल्शियम रिच चीजों को डाइट में शामिल करके आप हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ दिल को हेल्दी और मसल्स को स्ट्रांग रख सकती हैं. मगर ध्यान रहे कैल्शियम युक्त चीजों का अधिक सेवन करने से आपको दिल की बीमारी भी हो सकती है. इसलिए कैल्शियम का सीमित मात्रा में सेवन करना बेहतर रहता है.

मैग्नीशियम

मैग्नीशियम को मिनरल्स का बेस्ट सोर्स माना जाता है. ऐसे में मैग्नीशियम से भरपूर आहार लेने से शरीर का ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है. वहीं पाचन तंत्र को मजबूत बनाने और गैस या एसिडिटी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी मैग्नीशियम रिच चीजों का सेवन बेस्ट होता है.

विटामिन डी

शरीर में विटामिन डी की कमी होने से डायबिटीज, ब्रेस्ट कैंसर और दिल की बीमारी होने का खतरा रहता है. वहीं विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है. ऐसे में विटामिन डी का सेवन करने के लिए मछली, डेयरी प्रोडक्ट्स, अनाज और सीरियल्स को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

ओमेगा 3 फैटी एसिड

40 के बाद महिलाओं को दिल की बीमारी, जोड़ों में दर्द, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने और स्ट्रोक पड़ने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में ओमेगा 3 फैटी एसिड खाने से इन सभी बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है. इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड को डाइट में एड करके आप कई गंभीर बीमारियों को भी मात दे सकती हैं.

इनसाइड

पंजाब के बंबीहा गैंग के 2 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 4 जिंदा कारतूस के साथ .32 कैलिबर की 5 पिस्टल बरामद

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब के बंबीहा गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों से 4 जिंदा कारतूस के साथ .32 कैलिबर की 5 पिस्टल बरामद किया। ये दोनों बंबीहा गैंग के सक्रिय सदस्य हैं।

नई दिल्ली। पंजाब के बंबीहा गिरोह के सक्रिय सदस्य गगनदीप सिंह व बलजीत सिंह को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 4 जिंदा कारतूस के साथ .32 कैलिबर की 5 सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल बरामद की गई।

गिरोह के सदस्य के लिए खरीदी थी पिस्टल

दिल्ली पुलिस ने बताया कि बरामद पिस्टल पंजाब में देवेंद्र बंबीहा गिरोह के सदस्यों को सप्लाई करने के लिए थी। बता दें कि गगनदीप सिंह ने मध्य प्रदेश में खरगोन के एक बन्दूक निर्माता-सह-आपूर्तिकर्ता से कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात के बंबीहा गिरोह के संचालकों के निर्देश पर पिस्तौलें खरीदीं।

स्पेशल सेल ने किया गिरोह का भंडाफोड़

देवेंद्र बंबीहा गिरोह की लॉरेंस बिश्नोई-गोल्डी बराड़ के गिरोह के साथ भयंकर प्रतिद्वंद्विता है, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब और अन्य राज्यों में गैंगवार में उनके कई सहयोगी मारे गए। इंस्पेक्टर के नेतृत्व में स्पेशल सेल की टीम शिव कुमार व इंस्प्र. एसीपी अत्तर सिंह की देखरेख में पवन कुमार ने सिंडिकेट के दो प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार कर एक अंतरराज्यीय अवैध आग्नेयास्त्र सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है।

गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी कुख्यात देवेंद्र बंबीहा गिरोह (पंजाब के लॉरेंस बिश्नोई-गोल्डी बराड़ गिरोह का एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह) के सक्रिय सदस्य हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों से पूछताछ और हथियारों की तस्करी के विभिन्न पुराने मामलों की जांच के आधार पर यह खुलासा हुआ है कि पंजाब में हथियार हासिल करने का चलन बढ़ रहा है।

कनाडा और UAE से ट्रांसफर हुआ पैसा

पिछले 2-3 वर्षों के दौरान इन गैंगस्टरों और अपराधियों को एमपी स्थित हथियार आपूर्तिकर्ताओं से अक्सर फायरआर्म्स मिल रहे हैं। पंजाब के अपराधियों द्वारा मध्य प्रदेश से हथियार खरीदने के मामलों की जांच के दौरान अर्शदीप उर्फ दल्ला, हनी और यादविंदर सिंह के नाम बार-बार सामने आए हैं। तीन लोगों ने मप्र के हथियार आपूर्तिकर्ताओं के बैंक खातों में सीधे कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात से पैसा ट्रांसफर किया।

दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार, जनरेटर चलाने और कोयला-लकड़ी जलाने की मिली छूट

दिल्ली-NCR में पिछले कुछ दिनों से तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसे में हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल रहा है

एनटीवी संवाददाता

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से तेज हवाओं के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए ग्रेप II के प्रतिबंध को दिल्ली-NCR में हटा दिया गया है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धीरे-धीरे सर्दी खत्म होती दिखाई दे रही है। सर्दी का प्रकोप कम होते ही दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल रहा है। गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में मध्यम श्रेणी की हवा दर्ज की गई।

न्यूनतम तापमान में वृद्धि की उम्मीद

दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की उम्मीद है। बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 21.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाओं का असर समाप्त होने की उम्मीद थी और अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की उम्मीद थी।

दिल्ली-NCR में ग्रेप दो के प्रतिबंध हटे

बता दें कि दिल्ली-NCR में पिछले कुछ दिनों से तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसे में हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल रहा है। हवा की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए दिल्ली-NCR में बुधवार को ग्रेप दो के तमाम प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। ग्रेप के दूसरे चरण के प्रतिबंध को हटते ही दिल्ली-NCR में 105 दिन बाद डीजल जनरेटर सेट पर प्रतिबंध हटा दिया।

हवा की गुणवत्ता में हो रहा सुधार

गौरतलब है कि दिल्ली की हवा में सुधार होता दिखाई दे रहा है। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 207 था। इसके बाद मंगलवार को हवा में और सुधार देखने को मिला है। मंगलवार को 192 AQI दर्ज किया गया। बुधवार को और नीचे गिरकर 164 पर आ गया। इसी के मद्देनजर शाम को सीएक्यूएम की उप समिति ने बैठक की और मौसम एवं प्रदूषण की सारी स्थिति पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया।

LG हर फाइल पर लगा देते बेतुके ऑब्जेक्शन, उपराज्यपाल के साथ खींचतान के बीच बोले CM अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस की। केजरीवाल ने शिक्षकों को विदेश में ट्रेनिंग पर भेज जाने के मामले को लेकर उपराज्यपाल पर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि LG हर फाइल पर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली में शिक्षकों को विदेश में ट्रेनिंग पर भेजने को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के बीच लगातार खींचतान देखने को मिल रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार शिक्षकों को विदेश में ट्रेनिंग पर भेजने के लिए अड़ी है। आम आदमी पार्टी एलजी पर सरकार के काम में रोड़ा अटकाने का आरोप लगा रही है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने LG को घेरा

गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसी मुद्दे पर प्रेस कांफ्रेंस की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस में शिक्षकों को फिनलैंड नहीं जाने देने के मुददे पर एलजी को घेरा। उन्होंने कहा कि अब तो दूसरे राज्यों की सरकारें भी अपने शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने लगी हैं, लेकिन दिल्ली में एलजी इस फाइल पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं।

केजरीवाल ने कहा कि देश के किसी भी राज्य में चुनी हुई सरकार को अपनी सभी फाइलें एलजी को नहीं भेजनी होती। किन्तु दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट को भी ठेंगा दिखा, जीएनसीटीडी एक्ट में ही बदलाव कर दिया।

LG किसी भी फाइल को रोक देते हैं-CM

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि अब सरकार की मजबूरी बन गया है कि एलजी को हर फाइल भेजी जाए। मतलब, काम अब हो ही नहीं पाएंगे, एलजी जब चाहें, किसी भी फाइल को रोक देंगे। मेरा एलजी साहब से अनुरोध है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में चल रही सुनवाई में अपना अंतिम निर्णय नहीं देते, तब तक फाइल न रोकें।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में शिक्षा का कायाकल्प होना शुरू हो गया है। 4 फरवरी को पंजाब के 36 प्रिंसिपल ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। दिल्ली के 30-30 प्रिंसिपल ट्रेनिंग के लिए दिसंबर-मार्च में विदेश जाने थे, लेकिन LG के बेतुके ऑब्जेक्शन की वजह से ट्रेनिंग पर नहीं जा पाएंगे।

LG हर फाइल पर लगा देते बेतुके ऑब्जेक्शन

सीएम ने आगे कहा कि 2018 को संविधान पीठ ने कहा था कि कोई फाइल LG के पास नहीं जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने संविधान के ख़िलाफ़ जाकर क़ानून पास किया। अब LG हर फ़ाइल पर बेतुके Objections लगा कर रोक देते हैं। हम SC में गए हैं, हमें उम्मीद है कि SC इस ग़लत क़ानून को रद्द करेगी।

पिछले ढाई महीनों कैदियों से जब्त हुए 348 फोन जेलों में सुधार के लिए 23 सूत्रीय एजेंडे पर हो रहा कार्य

तिहाड़ जेल मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जेल महानिदेशक संजय बेनीवाल ने कहा कि दिल्ली की जेलों में व्याप्त अव्यवस्था को पूरी तरह ठीक करने के लिए जेल प्रशासन 23 सूत्रीय एजेंडे पर कार्य कर रहा है।

नई दिल्ली। दिल्ली की जेलों में व्याप्त अव्यवस्था को पूरी तरह ठीक करने के लिए जेल प्रशासन 23 सूत्रीय एजेंडे पर कार्य कर रहा है। 23 सूत्रीय एजेंडे में जेलों में कैदियों द्वारा मोबाइल के इस्तेमाल को पूरी तरह से रोकने की चुनौती सबसे अहम है।

तिहाड़ जेल मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जेल महानिदेशक संजय बेनीवाल ने कहा कि पिछले ढाई महीने के दौरान जेलों से 348 मोबाइल बरामद किए गए हैं। हम लोगों ने जेल में एक सूचना तंत्र विकसित किया है। सभी जेल अधीक्षक इस तंत्र से मिली जानकारी का उपयोग कर छापेमारी कर रहे हैं, जिससे मोबाइल के इस्तेमाल पर अंकुश लग रहा है।

कैदियों के सहभागियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

जेल महानिदेशक ने कहा कि 1 फरवरी को जेल संख्या तीन में छापेमारी की गई थी और 18 मोबाइल बरामद किए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि छापेमारी का सिलसिला आने वाले समय में जारी रहेगा। इतनी बड़ी तादाद में मोबाइल कहां से आ रहे हैं और इसमें किस-किस की सहभागिता है, इसे लेकर बरामदगी के समानांतर जांच प्रक्रिया चल रही है। जिसकी भी सहभागिता सामने आएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

शिक्षकों को विदेश में ट्रेनिंग पर भेजने का मामला

कार्यक्रम के दौरान जेल महानिदेशक ने जेलों में कैदियों के सुधार से जुड़े कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए कहा, "हम न सिर्फ बाहरी बल्कि कैदियों के आचरण में आंतरिक सुधार भी चाहते हैं। कोई भी सुधार तब तक पूर्ण नहीं होगा, जब तक इंसान अंदर से अच्छे व बुरे में फर्क कर बुराई से दूर रहने का मन नहीं बना लेता। कैदियों के मानसिक व वैचारिक बदलाव के लिए हमलोग आर्ट आफ लिविंग संस्था के साथ मिलकर एक बृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि एक वर्ष के भीतर जेलों में बंद सभी कैदियों तक इस कार्यक्रम का लाभ मिले।

आर्ट आफ लिविंग के साथ होने वाले कार्यक्रम के नतीजों पर भी हम विचार करेंगे कि हम अपने उद्देश्य को पाने में कितने सफल हुए। कैदियों की काउंसिलिंग से लेकर उनके अंदर छिपे सकारात्मक हुनर को हमलोग और निखारने में जुटे हैं। कौशल विकास योजना के तहत करीब दो हजार कैदियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।"

112 की तर्ज पर शुरू होगा सूचना नंबर

महानिदेशक ने कहा कि हमारी कोशिश है कि जेल में कैदी अपनी समस्याओं की हमलोगों को तत्काल सूचित करे। इसके लिए हमलोग 112 नंबर की तर्ज पर कैदियों के लिए एक नंबर जारी करने जा रहे हैं ताकि कैदी इस नंबर पर डायल कर अपनी समस्या या किसी जानकारी से जेल अधिकारियों को तत्काल अवगत कराए। इससे जेलों में हमारा सूचना तंत्र मजबूत होगा। जब समस्याओं की जानकारी हमें सीधे और तत्काल मिलेगी तब हम समाधान की दिशा में भी तत्काल प्रयास शुरू कर देंगे।

अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे एलजी, शिक्षकों को फिनलैंड भेजने की अनुमति न देने पर बोले मनीष सिसोदिया

एनटीवी संवाददाता

सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार अड़ी हुई है। इसी कड़ी में गुरुवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने पंजाब सरकार के बहाने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर निशाना साधा है।

नई दिल्ली। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही है। ताजा मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने पंजाब सरकार के बहाने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर निशाना साधा है।

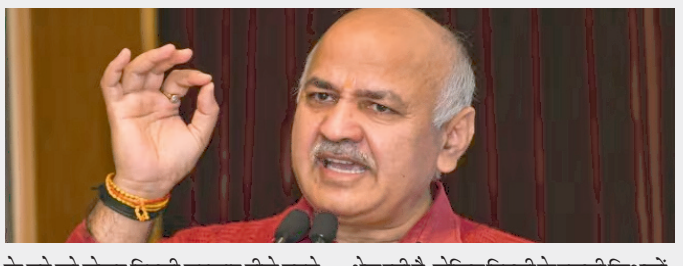

उन्होने कहा, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को अपनाते हुए पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार 36 टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेज रही है, लेकिन दिल्ली के एलजी शिक्षकों को फिनलैंड नहीं जाने दे रहे हैं, वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं।

सिसोदिया ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार एलजी के माध्यम से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों का भी हनन कर रही है। उन्होंने यह बातें आज गुरुवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। बता दें कि लंबे समय से शिक्षकों को ट्रेनिंग पर भेजने को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एलजी पर सरकार के काम में रोड़ा अटकाने का आरोप लगा रहे हैं।

एलजी पर फाइल रोकने का आरोप

गौरतलब है कि इस मामले को लेकर मनीष सिसोदिया ने मंगलवार यानी 31 जनवरी को उपराज्यपाल को एक चिट्ठी भी भेजी थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की फाइल 20 जनवरी से एलजी की टेबल पर अटकी पड़ी हैं। मैंने एलजी से उनसे पुनः अनुरोध किया है कि इस पर जल्द अपनी सहमति दें। फाइल रोकने और घुमाने के चक्कर में ट्रेनिंग का अगला राउंड भी रद्द होने के कगार पर है।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति को लेकर ED के आरोप पत्र पर लिया संज्ञान, आरोपितों के खिलाफ समन जारी

राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में ईडी के पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए सभी पांच आरोपितों के खिलाफ समन जारी किया है। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 23 फरवरी 2023 को होगी।

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में ईडी के पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए सभी पांच आरोपितों के खिलाफ समन जारी किया है। कोर्ट ने विनय बाबू, शरद रेड्डी, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और अमित अरोड़ा के खिलाफ समन जारी किया है। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी।

सीएम केजरीवाल ने ED की चार्जशीट को बताया फिक्शन: CM केजरीवाल ने ईडी द्वारा दायर की गई चार्जशीट को फिक्शन बताया है। केजरीवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि ईडी ने उनके पूरे कार्यकाल में करीब 5 हजार चार्जशीट दायर की होगी। केजरीवाल ने कहा कि यह सारे केस फर्जी होते है। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि ईडी का इस्तेमाल केवस सरकारें गिराने और विधायकों को खरीदने में किया जाता है। इसके अलावा केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर भी हमला बोला है।

क्या था मामला?

केजरीवाल सरकार दिल्ली में शराब नीति लेकर आई थी, जिसके तहत दिल्ली के शराब कारोबारी ग्राहकों को डिस्काउंटेड रेट पर शराब बेच रहे थे। दिल्ली के कई जगहों पर एक बोतल खरीदने पर दूसरी मुफ्त दी जा रही थी। इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला था।

चलती ट्रेन में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, लेकिन समय पर इलाज न मिलने पर शांत हो गई किलकारी

प्रयागराज से दिल्ली जा रही नई दिल्ली- पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन के जनरल कोच में बुधवार को मिर्जापुर से दिल्ली जा रही 35 वर्षीय प्रेरणा को दादरी के पास प्रसव पीड़ा होने लगी। अन्य महिला यात्रियों ने तुरंत प्रसव पीड़ा से कराहती प्रेरणा को पर्दे में रखकर प्रसव कराया।

गाजियाबाद। प्रयागराज से दिल्ली जा रही नई दिल्ली- पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन के जनरल कोच में बुधवार को मिर्जापुर से दिल्ली जा रही 35 वर्षीय प्रेरणा को दादरी के पास प्रसव पीड़ा होने लगी। अन्य महिला यात्रियों ने तुरंत प्रसव पीड़ा से कराहती प्रेरणा को पर्दे में रखकर प्रसव कराया।

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही ट्रेन में बच्चे की किलकारी गूंजी तो लोग खुश हो गए। बेटा पैदा होने पर खुशियां मनाई गईं। रेलवे अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई और रेलवे के अस्पताल में जच्चा-बच्चा को भेज दिया गया। यहां पर चिकित्सकों ने दोनों की हालत गंभीर बताते हुए जिला एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में रेफर कर दिया।

जिला अस्पताल भेजा

जिला एमएमजी अस्पताल प्रबंधन ने दोनों को जिला महिला अस्पताल भेज दिया। सीएमएस डा. संगीता गोयल ने बताया कि नवजात की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रेरणा की हालत ठीक है।

...तो बच जाती जान

उधर दोपहर बाद प्रेरणा के साथ यात्रा कर रहे बुजुर्ग मुहम्मद नन्नू ने नवजात बच्चे का हिंडन मोक्ष स्थली पर अंतिम संस्कार किया। बताया गया है कि जच्चा-बच्चा को सही समय पर उपचार मिल जाता तो नवजात की जान बच जाती।

बच्चे के लिफ्ट में फंसने पर डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निदेशक से मांगी रिपोर्ट, स्वजन की थी जांच की मांग

एनटीवी न्यूज

नोएडा में चाइल्ड पीजीआई की लिफ्ट में बच्चे के फंसने को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निदेशक से रिपोर्ट मांगी है। इस बात की जानकारी उपमुख्यमंत्री ने स्वयं अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। परिजनों ने मामले में जांच की मांग की थी।

नोएडा। सेक्टर-30 स्थित बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान (चाइल्ड पीजीआई) के आवासीय परिसर की लिफ्ट में दस वर्षीय बच्चे के 45 मिनट तक फंसने की घटना प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है। संस्थान के निदेशक से तीन दिन के अंतर घटना की जांच रिपोर्ट मांगी है।

लिफ्ट में 45 मिनट तक फंसा रहा बच्चा

इस बात की जानकारी उपमुख्यमंत्री ने स्वयं अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। दैनिक जागरण ने खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। ललित शर्मा ने प्रबंधन को दी शिकायत में बताया कि मंगलवार को पुत्र लिफ्ट के अचानक खराब होने से उसमें 45 मिनट फंसा रहा था।

जब लिफ्ट खुली तो बच्चा घबराकर बाहर निकला और चक्कर खाकर गिर गया। घटना से डरा सहमा बच्चा पूरी रात सो नहीं पाया। डर के कारण पूरी रात रोता रहा। उसे बुखार भी चढ़ गया था। स्वास्थ्यकर्मियों का आरोप है कि आवासीय परिसर में आए दिन लिफ्ट खराब रहती है। लिफ्ट खराब होने के संबंध में पूर्व में कई बार शिकायत की जा चुकी है।

शिकायत के बावजूद कोई कदम नहीं

शिकायत के बावजूद प्रबंधन ने कोई सख्त कदम नहीं उठायाा। जबकि लिफ्ट मरम्मत के नाम पर लगातार सरकारी धन का भुगतान हो रहा है। प्रबंधन ने भूतल पर ओपीडी एरिया के पास लिफ्ट लेने वाली जगह पर नमूने लेने व प्रथम तल पर टीकाकरण कक्ष बना दिया है। ऐसे में लाखों रुपये की लागत से लगी तीन लिफ्ट पर पर्दा डला है। भूतल से चौथे तल पर जाने के लिए एक साइड की लिफ्ट का उपयोग हो पा रहा है। ऊपरी तल पर जाने के लिए लोगों परेशानी होती है। वहीं प्रबंधन का कहना है कि लिफ्ट के मेंटनेंस पर प्रतिवर्ष 15 लाख रुपये का खर्च आता है। इस कारण एक तरफ की लिफ्ट बंद की है।

प्रॉपर्टी खरीद और वेबसाइट पर फर्जी मालिक बन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

प्रॉपर्टी खरीद और बिक्री की वेबसाइट पर फर्जी मालिक या ब्रोकर बनकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बुधवार को पुलिस ने चार अपराधियों को दबोच लिया। आरोपितों के कब्जे से एक एटीएम कार्ड सात फर्जी आधार कार्ड पासबुक और 20 हजार की नकदी बरामद हुई है।

नोएडा। प्रॉपर्टी खरीद और बिक्री की वेबसाइट पर फर्जी मालिक या ब्रोकर बनकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बुधवार को सेक्टर-39 कोतवाली पुलिस ने चार शातिर अपराधियों को दबोच लिया। आरोपितों के कब्जे से एक एटीएम कार्ड, सात फर्जी आधार कार्ड, पासबुक और 20 हजार की नकदी बरामद हुई है।

आरोपितों की पहचान बिहार के मुजफ्फरपुर के अमितेश मिश्रा, भोजपुर के मृत्युंजय चौबे, एक्सप्रेस-वे कोतवाली क्षेत्र स्थित नगला नगली गांव के अनिल चौहान और सलारपुर के पुष्पेंद्र के रूप में हुई है। गिरफ्त में आए चारों आरोपितों का काम विभाजित था।

अमितेश मिश्रा उर्फ करण ग्राहकों से बात कर फ्लैट या कामर्शियल प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए समय निर्धारित करने का काम करता था। पुष्पेंद्र ग्राहक को फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टी को मौके पर जाकर दिखाता था और फर्जी फ्लैट मालिक से फोन पर बात कराता था।

अनिल चौहान फर्जी फ्लैट मालिक बन कस्टमर से फोन पर बात करता था और फर्जी रेंट एग्रीमेंट तैयार कर एग्रीमेंट की छायाप्रति ग्राहक को देता था। मृत्युन्जय के खाते में रकम ट्रांसफर कराई जाती थी। इसके बाद चारों रकम का बराबर बंटवारा करते थे।

एडिशनल डीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि शातिर प्रॉपर्टी खरीद और ब्रिकी संबंधी मैजिकब्रिक्स, 99 एकर्स सहित अन्य वेबसाइट पर फ्लैट व कामर्शियल प्रॉपर्टी का फर्जी मालिक बन उसे किराये पर उठाने के लिए विज्ञापन डालते थे। विज्ञापन देखने के बाद जैसे ही ग्राहक शातिरों द्वारा उपलब्ध कराए गए नंबर पर फोन करता था, आरोपित उसे झांसे में लेते थे।

बीते तीन माह के भीतर आरोपितों ने इसी प्रकार से कुल सात लाख रुपये की ठगी की है। अभी तक कुल नौ लोगों के साथ ठगी की बात सामने आई है। शातिरों का आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है।

गलत नाम और पता डालकर करते थे ठगी

एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि आरोपित रियल एस्टेट की साइट पर गलत नाम और मोबाइल नंबर डालकर आइडी बनाते थे और फ्लैट दिलाने का झांसा देकर ठगी करते थे। कुछ दिनों से पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि आनलाइन साइट पर किराये पर फ्लैट दिलाने के नाम पर ठगी की जा रही है। जांच के दौरान चारों की संलिप्तता इसमें पाई गई।

हफ्तेभर में आरोप पत्र के बाद 140 दिनों में ही हो रही सजा, फिर भी हैवानों में नहीं दिख रहा खौफ

मासूमों से हैवानियत के मामलों में पुलिस प्रभावी पैरवी कर रही है। इसी का नतीजा है कि निवाड़ी थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में सात दिन में ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे।

गाजियाबाद। मासूमों से हैवानियत के मामलों में पुलिस प्रभावी पैरवी कर रही है। इसी का नतीजा है कि निवाड़ी थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में सात दिन में ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया। खोड़ा थाना पुलिस ने पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत कर 140 दिन में ही किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो सगे भाईयों को आजीवन कारावास की सजा दिला दी। बावजूद इसके हैवानों के मन में डर नहीं बैठ रहा है। एक के बाद एक बच्चियां व बच्चे हैवानियत का शिकार हो रहे हैं। इन पर अंकुश लगाने के लिए अभिभावकों का जागरूक होना भी बहुत जरूरी है।

केस एक

निवाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में पड़ोसी युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। उसके तीन साथियों ने अश्लील वीडियो बनाया। मामले में पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सात दिन में ही न्यायालय में 50 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

केस दो

इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र में 11 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस ने साक्ष्य एकत्र किए। उसके आधार पर 18 दिन में ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

केस तीन

खोड़ा थाना क्षेत्र में 11 साल की बच्ची के साथ दो सगे भाईयों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। बच्ची ने स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। पुलिस ने इस मामले में पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर 22वें दिन न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। दोनों भाईयों को 140 दिन में आजीवन कारावास की सजा हो गई।

केस चार

साहिबाबाद कोतवाली क्षेत्र में घर के बाहर

खेल रही चार साल की बच्ची को एक युवक ने अगवा करके दुष्कर्म किया। उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में 16वें दिन 175 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया। उसमें 28 गवाहों व इलेक्ट्रानिक साक्ष्य शामिल किए। बृहस्पतिवार को मामले में न्यायालय सजा सुनाएगी।

नहीं पैदा हो रहा भय

वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. संजीव त्यागी ने बताया कि ज्यादातर बच्चों के साथ मुंहबोले रिश्तेदार या पड़ोसी हैवानियत करते हैं। ऐसे लोगों को सजा से डर नहीं लगता है। उनके मन में रहता है कि बच्चे डर के कारण किसी को यह बात बताएंगे नहीं। ऐसे में अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को जागरूक करें। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में जल्दी सजा मिलने का प्रभाव भी समाज पर दिखेगा। अवश्य ही ऐसे मामलों में कमी आएगी।

अभिभावक का सचेत रहना जरूरी

मनोरोग विशेषज्ञ वसुंधरा शर्मा ने बताया कि नर्सरी से ही बच्चों को गुड व बैड टच की जानकारी दें। बच्चा यदि कोई बात करे तो उससे पुलिस बनकर न पूछे यानी सख्ती से पेश न आएं। बल्कि उसका दोस्त बन जाएं। उससे बातचीत करके झिझक दूर करें। इससे वह खुलकर बात करेगा। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ गलत काम करेगा तो वह स्वजन को बताएगा। इससे शुरू में ही संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई हो जाएगी।

पुलिस भी सतर्क

पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन डा. दीक्षा शर्मा ने बताया कि ऐसे मामलों में प्रभावी पैरवी करके दोषियों को सजा दिलाई जा रही है। इससे इस तरह की घिनौनी हरकत करने के बारे में सोचने से भी लोग डरेंगे। इसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से समय-समय पर बच्चों को जागरूक करने के लिए कार्यशालाएं की जा रही हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय है।

हैवानित के कुछ प्रमुख मामले

- 28 जनवरी: लिंक रोड थाना क्षेत्र में चार साल की बच्ची के साथ रिश्ते के बाबा ने दुष्कर्म किया।
- 28 जनवरी: लोनी बार्डर थाना क्षेत्र में 13 साल की किशोरी के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म किया।
- 28 जनवरी : लोनी कोतवाली क्षेत्र में मदरसे के मौलाना ने 12 साल के बच्चे के साथ कुकर्म किया।
- 27 जनवरी: लिंक रोड थाना क्षेत्र में सात साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म किया।

आरोपित ने निवेश के नाम पर उन्हें 10 प्रतिशत के मुनाफे का लालच दिया था।

- 11 जनवरी: इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र में 11 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म किया।
- 24 दिसंबर : निवाड़ी थाना क्षेत्र में 17 साल की किशोरी के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म किया।
- एक दिसंबर : साहिबाबाद कोतवाली क्षेत्र में चार साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई।
- पांच सितंबर : खोड़ा थाना क्षेत्र में 11 साल की बच्ची के साथ सगे भाईयों ने दुष्कर्म किया।
- 15 अक्टूबर: लिंक रोड थाना क्षेत्र में ढाई साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म।

बारात चढ़ने के दौरान दूल्हे के ताऊ से लूटा लाखों का बैग, रखे थे गहने और कैश

बाइक सवार दो लुटेरों ने मंगलवार रात टीला मोड़ थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर में बारात की चढ़त के दौरान दूल्हे के ताऊ का रुपये व गहनों से भरा बैग लूट लिया। उन्होंने वारदात स्थल से चंद कदम की दूरी पर स्थित सिकंदरपुर पुलिस चौकी में सूचना दी।

गाजियाबाद। बाइक सवार दो लुटेरों ने मंगलवार रात टीला मोड़ थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर में बारात की चढ़त के दौरान दूल्हे के ताऊ का रुपये व गहनों से भरा बैग लूट लिया। उन्होंने वारदात स्थल से चंद कदम की दूरी पर स्थित सिकंदरपुर पुलिस चौकी में सूचना दी।

पुलिसकर्मियों ने लुटेरों का पीछा करने के बजाय लापरवाही बरती। उन्हें टीला मोड़ थाने जाकर शिकायत करने की सलाह देकर टरका दिया। वहीं, कौशांबी थाना क्षेत्र के वैशाली सेक्टर-पांच में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर के बेटे से मोबाइल लूट लिया।

उल्टी दिशा से आए लुटेरे

सरस्वती विहार, खोड़ा के मंगूलाल शर्मा के भतीजे अभिषेक शर्मा की मंगलवार रात में शादी थी। टीला मोड़ थाना क्षेत्र के ग्रीन वैली फार्म हाउस-दो, सिकंदरपुर में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। रात करीब 10 बजे बारात की चढ़त हुई। बराती नाचते-गाते द्वारचार के लिए निकल पड़े।

रास्ते में सिकंदरपुर पुलिस चौकी के पास उल्टी दिशा से आए बाइक सवार दो लुटेरों ने मंगूलाल का बैग लूट लिया। उसमें करीब 1.20 लाख रुपये और करीब एक लाख से अधिक के गहने थे। उन्होंने शोर मचाया। दौड़कर पुलिस चौकी में पहुंचे। सुनवाई नहीं होने पर टीला मोड़ थाने में जाकर शिकायत दी। पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।

समोसा लेने गए किशोर से लूट

वैशाली सेक्टर-पांच में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के उपायुक्त विकास कृष्ण बंसल का बेटा हरी कृष्ण बंसल सोमवार शाम करीब सात बजे पास की दुकान से समोसा लेने गया। इस बीच बाइक सवार दो लुटेरों ने उसका करीब 75 हजार रुपये मोबाइल लूट लिया। मोबाइल उसके नाना के नाम पर था। उसने पुलिस को शिकायत दी। कौशांबी थाना में मंगलवार को अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन डा. दीक्षा शर्मा ने बताया कि दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज करके जांच की जा रही है।

बेखौफ थे लुटेरे

सिकंदरपुर में मंगूलाल शर्मा के भतीजे की बारात के आगे दो और बारात चल रही थी। काफी भीड़भाड़ थी। पास में सिकंदरपुर पुलिस चौकी थी। बावजूद इसके लूट हो गई। इसी तरह वैशाली में भीड़भाड़ वाले स्थान पर हरी कृष्ण बंसल से लूट हुई। इन दोनों वारदात से स्पष्ट हो गया कि लुटेरे बहुत ही बेखौफ थे। उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं था।

पुलिस फेल

क्षेत्र में लुटेरों पर अंकुश लगाने के लिए क्यूआरटी गठित की गई है। यह क्षेत्र में भ्रमणशील रहती है। चीता मोबाइल सक्रिय किए गए हैं। जगह-जगह चेकिंग व गश्त का दावा किया जा रहा है। बावजूद इसके लूट पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इससे पुलिस की सारी कवायदों की पूरी तरह से पोल खुल रही है।

इनसाइड

नोएडा की महिला ने मांगी इच्छा मृत्यु, राष्ट्रपति को लिखा पत्र; बिल्डर से फ्लैट न मिलने से है नाराज

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक बिल्डर परियोजना में फ्लैट न मिलने से नाराज महिला ने राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु दिए जाने की मांग की है। महिला का आरोप है कि वह शासन-प्रशासन यूपी रेरा व बिल्डर कार्यालय के चक्कर काटकर थक चुकी है।

नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक बिल्डर परियोजना में फ्लैट न मिलने से नाराज महिला ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु दिए जाने की मांग की है। महिला का आरोप है कि वह शासन-प्रशासन, यूपी रेरा व बिल्डर कार्यालय के चक्कर काटकर थक चुकी है, लेकिन उसे कहीं से भी न्याय नहीं मिला है। जीवन भर की जमा पूंजी वह बिल्डर को सौंप चुकी है। उसके बाद भी उसे आशियाना नहीं मिला। यदि सरकार अथवा प्रशासन उसे घर नहीं दिला सकते तो इच्छा मृत्यु दें दे।

2017 में बुक कराया था फ्लैट

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इकोविलेज तीन में महिला अपने परिवार के साथ किराये पर रहती हैं। उन्होंने बताया कि वह मूलरूप से कोलकता की रहने वाली है, लेकिन पिछले 12 साल से दिल्ली में ही रह रही हैं। उन्होंने वर्ष 2017 में ग्रेनो वेस्ट स्थित सुपरटेक स्पोर्ट विलेज में फ्लैट बुक कराया था।

2019 तक फ्लैट पर कब्जा देने का किया था वादा

बिल्डर ने फ्लैट बुकिंग के दौरान 2019 तक फ्लैट पर कब्जा देने का वादा किया था, लेकिन बिल्डर बायर एग्रीमेंट के मुताबिक उन्हें देय समय में घर नहीं मिला। उसके बाद कोरोना में उनके पति का देहांत हो गया। वह बूढ़ी सास व अपनी आठ साल की बेटी के साथ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में किराये पर रह रही हैं। पति की मृत्यु के बाद पूरा परिवार मानसिक प्रताड़ना से पीड़ित है।

सरकार और प्रशासन से भी लगाई गुहार

शासन-प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी उन्हें फ्लैट नहीं मिला। वह बिल्डर को फ्लैट की कीमत का तकरीबन 80 प्रतिशत भुगतान कर चुकी है। उन्होंने बताया कि 25 लाख में उन्होंने फ्लैट खरीदा था। फ्लैट की कीमत का 20 लाख रुपये वह बिल्डर को अदा कर चुकी है। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने थक हारकर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है।

भारत में सुप्रीम कोर्ट ने दिया इच्छामृत्यु का हक (Euthanasia right in India)

सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान से मरने के अधिकार को मान्यता देते हुए भारत के लोगों को जिंदगी की वसीयत (लिविंग विल) में इच्छामृत्यु का हक 2018 में दे दिया था। उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति को निष्क्रिय इच्छामृत्यु का कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया है। दूरगामी परिणामों वाला यह ऐतिहासिक फैसला मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुनाया था।

कोर्ट ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले सम्मान से जीवन जीने के अधिकार में सम्मान से मरने का अधिकार शामिल है। बेल्जियम, लग्जमबर्ग, हॉलैंड, स्विटजरलैंड, जर्मनी और अमेरिका के ओरेगन और वाशिंगटन राज्यों में इसको कानूनी मान्यता मिली हुई है।

इच्छामृत्यु दो प्रकार की होती है (Types of Euthanasia)

पैसिव यूथेनेसिया या निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia)

जीवन रक्षण प्रणाली को हटाकर प्राकृतिक रूप से मौत के लिए छोड़ दिया जाता है। दवाएं बंद कर दी जाती हैं। खाना और पानी बंद कर दिया जाता है।

एक्टिव यूथेनेसिया या सक्रिय इच्छामृत्यु (Active Euthanasia)

मौत के लिए सीधे कदम उठाए जाते हैं। इसमें जहरीला इंजेक्शन भी शामिल हो सकता है।

Land Rover ने किया अपनी नई Range Rover Velar को पेश, सिग्नेचर डिजाइन में नहीं

Land Rover ने किया अपनी नई Range Rover Velar का अनावरण, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑटोमेकर के Pivi प्रो सिस्टम द्वारा संचालित है और वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट के साथ ओवर-द-एयर (OTA) के साथ आता है। समें मोबाइल चार्ज करने के लिए वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है।

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स की लग्जरी ब्रिटिश कार निर्माता कंपनी marquee Land Rover ने नई रेंज रोवर वेलार (Range Rover Velar)का अनावरण कर दिया है। इसके साथ ही इसे कई अपडेट भी मिले हैं। लग्जरी SUV की स्टाइलिंग आउटगोइंग मॉडल जैसी ही है, लेकिन इसमें किए गए थोड़े से बदलाव इसे और आकर्षक बनाते हैं। सीधे और सरल शब्दों में कहे तो कंपनी ने इसके सिग्नेचर डिजाइन में कोई खास बदलाव नहीं की है। नई रेंज रोवर वेलार में किए गए बदलावों के बारे में बात करते हुए, ये नई एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट तेज हेडलैम्प्स के साथ आती है, जो पूरी तरह से काले रंग की थीम वाली फंट्र ग्रिल को फ्लैक करती है। इसके रियल प्रोफाइल की बात करें तो इसमें अपडेट बम्पर मिलता है जहां निचले हिस्से को एक नया रूप दिया है। SUV का साइड प्रोफाइल प्री-फेसलिफ्ट वर्जन जैसा ही है। कार अब मैटेलिक वेरेसिन ब्लू या प्रीमियम मैटेलिक ज़डार ग्रे जैसे कलर ऑप्शन के साथ उपलब्ध है।

केबिन के अंदर हुए बड़े बदलाव

इस एसयूवी के केबिन के अंदर बड़े बदलाव किए गए है। नई रेंज रोवर वेलार में फ्लोटिंग कर्व्ड ग्लास डिस्प्ले के साथ लैंड रोवर का शानदार 11.4 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो प्रीमियमनेस को बढ़ाता है। इसके साथ ही ये अपडेट एसयूवी को रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट के समान लाइन में भी आता है। वाहन निर्माता कंपनी का दावा है कि इस बदलाव की बदौलत कार के अंदर लोग होम स्क्रीन के सिर्फ दो टैप के साथ कार में उपलब्ध सभी फीचर्स को 80 प्रतिशत तक उपयोग कर सकेंगे।

फीचर्स

टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑटोमेकर के Pivi प्रो सिस्टम द्वारा संचालित है और वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट के साथ ओवर-द-एयर (OTA) के साथ आता है। इसमें मोबाइल चार्ज करने के लिए वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है। केबिन के अंदर अपडेट लेदर-फ्री अपहोल्स्ट्री मिलता है, नए वेलार के लिए तीन नए लेदर इंटीरियर थीम उपलब्ध हैं। इसमें एक ऑप्शन क्लाउड, रेवेन ब्लू और डीप गार्नेट। लैंड रोवर ने स्टीयरिंग व्हील, एयर वेंट्स और सेंटर कंसोल सराउंड पर मूनलाइट क्रोम एक्सेंट भी लगाए गए हैं। इंजन की बात करें तो इसमें प्लग-इन हाइब्रिड वेरिएंट को 13.6 kWh से बढ़ाकर 19.2 kWh की क्षमता के साथ बैटरी अपग्रेड मिला है। जो इसकी रेंज को बढ़ाता है।

इनसाइड

सेफ्टी में नो कॉम्प्रोमाइज और अपडेटेड इंजन के साथ आएगी Hyundai की Alcazar, Creta और Venue

Hyundai Creta और Alcazar में अब छह एयरबैग इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण वाहन स्थिरता हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल रियर डिस्क ब्रेक सीट बेल्ट और ISOFIX भी मिलता है।हाल के दिनों में अपडेट ऑरा और ग्रैंड i10 Nios को लॉन्च किया है।

नई दिल्ली। Hyundai Motor India Limited (HMIL) भारतीय बाजार में अपनी कारों को समय के साथ और नियमों के साथ अपडेट करती रहती है। आपको बता दे कंपनी ने अपने वाहनों को BS6 RDE नॉर्म्स से पहले अपडेट करना शुरू कर दिया है। वाहन निर्माता कंपनी ने हाल के दिनों में अपडेट ऑरा और ग्रैंड i10 Nios को लॉन्च किया है। इसका ये मतलब है कि वेन्यू, अलकाजार और क्रेटा अब ज्यादा सेफ्टी इक्विपमेंट, फीचर्स और अपडेटेड इंजन के साथ आएंगे।

Hyundai Creta और Alcazar

आपको बता दे Hyundai Creta और Alcazar में अब छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण, वाहन स्थिरता प्रबंधन, हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, रियर डिस्क ब्रेक, सीट बेल्ट और ISOFIX भी मिलता है। वहीं Hyundai Venue है जो अब S (O), SX और SX (O) वेरिएंट के साथ आती है जो चार एयरबैग के साथ आती है।

फीचर्स

फीचर्स के तौर पर इस एसयूवी में आइडल स्टॉप एंड गो (आईएसजी) सुविधा मिलती है जो स्टॉप और गो ड्राइविंग स्थितियों के दौरान काम आती है। इसके कारण इंजन कैपेसिटी भी बढ़ती है। दूसरी ओर,हुंडई क्रेटा अब 60:40 स्प्लिट रियर सीट से लैस है।

Hyundai Venue

Hyundai Venue अब 1.5-लीटर U2 CRDi डीजल इंजन से लैस है जिसे वेरिएबल जियोमेट्री टर्बोचार्जर मिलता है। यह 113 बीएचपी और 250 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा, HMIL की 2023 SUV रेंज अब ऐसे इंजन के साथ आएगी जो E20 फ्यूल-रेडी और RDE कंप्लेंट हैं।

कंपनी का बयान

हुंडई मोटर इंडिया के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री तरुण गर्ग ने MY'23 एसयूवी रेंज लॉन्च पर कहा कि हमने हमेशा ग्राहको के सहूलियत के हिसाब से अपनी कारों को डिजाइन किया है। इसके साथ ही हम सरकार के निर्देश के साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं और सुनिश्चित किया है कि हमारे पावरट्रेन आरडीई के अनुरूप हों और ई20 ईंधन तैयार हो ।

प्रदूषण को लेकर Renault कंपनी हुई सख्त, कंपनी करेगी BS VI उत्सर्जन मानदंडों के दूसरे चरण को पूरा

इस साल 1 अप्रैल से वाहनों में ऑन-बोर्ड सेल्फ-डायग्नोस्टिक डिवाइस होने की जरूरत होगी ताकि लोगों की रियल टाइम ड्राइविंग एमिशन लेवल पर नजर रखी जा सकी। कंपनी की पूरी रेंज BS VI उत्सर्जन मानदंडों के दूसरे चरण को पूरा करेगी।

नई दिल्ली। प्रदूषण दिन पर दिन काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। इसको लेकर सरकार काफी सख्त हो चुकी है। वहीं इसी को देखते हुए वाहन निर्माता कंपनी रेनॉल्ट ने कहा कि देश में आने वाले उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए अपने प्रोडक्ट को अपडेट करेगी। आपको बता दें Kiger, Triber और Kwid सहित कंपनी की पूरी रेंज BS VI उत्सर्जन मानदंडों के दूसरे चरण को पूरा करेगी, जो इस साल 1 अप्रैल से लागू होगा।

बीएस VI मानदंड

वाहन निर्माता कंपनी ने कहा कि बीएस VI मानदंडों के दूसरे चरण के इंप्लीमेंट के साथ, सभी कारें सेल्फ-डाइगोर्नस्टिक व्हीकल उपकरण से लैस होंगी। ये डिवाइस ड्राइविंग के दौरान वाहन के उत्सर्जन स्तर की लगातार निगरानी करेगा, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण उत्सर्जन उपकरणों जैसे कैटेलिटिक कनवर्टर और ऑक्सीजन सेंसर के साथ।

रेनॉल्ट इंडिया

आपको बता दे रेनॉल्ट इंडिया ऑपरेशंस कंट्री के सीईओ और प्रबंध निदेशक वेंकटराम मामिलपल्ले ने कहा, इनए बीएस VI स्टेप 2 के अनुरूप पेट्रोल इंजनों की रेंज में उत्सर्जन में पर्याप्त कमी सुनिश्चित होगी, जिससे सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में काफी योगदान होगा। इसके साथ ही उन्होने कहा कि उत्पाद लाइन अप में अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताएं भी जोड़ा जाएगी।

सेफ्टी फीचर

कंपनी का मानना है कि सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और हमारी नई 2023 रेंज में नई श्रेणी की सुरक्षा सुविधाओं की भी शुरुआत होगी। जो भारत के लोगों के लिए सबसे उच्च सुरक्षा होगी उसे ही हम अपनाएगें। पूरी रेनॉल्ट रेंज अब सुविधाओं के रूप में इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता कार्यक्रम (ESP), हिल स्टार्ट असिस्ट (HSA), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) से सुसज्जित है।

इस साल 1 अप्रैल से वाहनों में ऑन-बोर्ड सेल्फ-डायग्नोस्टिक डिवाइस होने की जरूरत होगी ताकि लोगों की रियल टाइम ड्राइविंग एमिशन लेवल पर नजर रखी जा सकी। एमीशन पर नजर रखने के लिए डिवाइस कैटेलिटिक कनवर्टर और ऑक्सीजन सेंसर जैसे उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए लगातार प्रमुख भागों की निगरानी करेगा।

Tata की गाड़ियों को खरीदना होगा महंगा, Safari से लेकर Punch तक की बढ़ी कीमत

हाल के दिनों नें मारुति सुजुकी ने भी अपने सभी मॉडलों की कीमत में करीब1.1फीसदी की बढ़ोतरी की है। इसके कारण ही ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि आने वाले दिनो में कई कंपनियां भी अपने कारों कीमत को बढ़ाएगी।

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने अपनी यात्री वाहनों (पैसेंजर व्हीकल) के लिए अपने ICE पोर्टफोलियो में कीमतों में बढ़ोतरी की है। कीमत में बढ़ोतरी को लेकर कंपनी ने ये कहा कि बढ़ोतरी नियामकीय बदलावों और समग्र इनपुट लागत में बढ़ोतरी के कारण और बढ़ी हुई कॉस्ट के कारण किया गया है। कंपनी ने कहा कि वेरिएंट के आधार पर भारित औसत वृद्धि 1.2% होगी।

कीमत में हुई बढ़ोतरी

आपको बता दे बढ़ते कीमत के कारण इसके पीछे प्रभावित होने वाले मॉडल में Tata Tiago, Punch, Tigor, Altroz, Nexon, Harrier और Tata Safari शामिल हैं। वहीं इन बढ़ती कीमतों का असर पेश की जाने वाली इलेक्ट्रिक कारों पर कोई असर

नहीं पड़ेगा। हाल के दिनों नें मारुति सुजुकी ने भी अपने सभी मॉडलों की कीमत में करीब 1.1 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इसके कारण ही ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि आने वाले दिनो में कई कंपनियां भी अपने कारों कीमत को बढ़ाएगी।

Tiago EV कीमत

हाल के दिनों में भारतीय बाजार में टाटा मोटर्स ने अपनी Tiago EV को भारतीय बाजार में 8.49 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया है। इसे कुल चार वेरिएंट्स XE, XT, XZ+ और XZ+ Tech Lux में पेश किया गया है। Tiago EV में बैटरी और मोटर पर धूल और पानी के रजिस्टेंस के लिए IP67 रेटिंग के साथ दो लिथियम-आयन बैटरी पैक विकल्प - 19.2kWh और 24kWh मिलते हैं। 19.2kWh की बैटरी में 250km की MIDC रेंज का दावा किया गया है, जबकि बड़ी बैटरी को 315km की MIDC रेंज का दावा किया गया है।

फीचर्स

फीचर्स के तौर पर इस कार में 45 कनेक्टेड कार फीचर्स, हिल स्टार्ट और डिसेंट असिस्ट, TPMS, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और क्रूज कंट्रोल के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। Tiago EV में Ziptron इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है जो बड़े बैटरी पैक में 74hp की पावर और 114Nm का टार्क और छोटे बैटरी पैक में 61hp और 110Nm का टॉर्क जनरेट करती है।

जी भर कर जियो

पीके खुराना

यह एक लंबी मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा है, पर इसकी शुरुआत हर उम्र में संभव है। मानसिक शांति और संतुलन की बहुत छोटी सी और आसान शुरुआत तो सिर्फ यहां से हो सकती है कि हम हर तीन घंटे बाद आराम से बैठ कर लंबे सांस लेने की आदत डालें और जब कभी तनाव या चिंता में हों तो बैठ जाएं और गहरे लंबे सांस लें।

आज जब मैं उस घटना पर विचार करता हूं तो मुझे समझ आता है कि उस ग्रामीण दंपत्ति ने कितनी सरलता से एक बहुत बड़े सच का खुलासा किया था। यदि हम किसी को पसंद नहीं करते, और उसकी प्रशंसा करते हैं तो हम काम तो अच्छा कर रहे हैं, पर हम खुद अच्छे नहीं बन पाये हैं। इससे हमारे मन-मस्तिष्क में तनाव रहता है, जो कई रोगों का कारण बनता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (वल्र्ड हैल्थ आर्गेनाइज़ेशन) ने एक एडवाइज़री जारी करके बताया है कि अगले 8 सालों में, यानी सन् 2025 तक 87 फीसदी भारतीय कैंसर के मरीज़ हो जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि भारत में बिकने वाला 68.7 प्रतिशत दूध सिंथैटिक या मिलावटी होता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चिकित्सकों की दृष्टि से देखें तो यह एक सच्चाई है ही, पर जरा और गहराई में जाएं तो हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। हमारा देश इस समय झगड़ालू प्रवृत्ति और मानसिक तनाव में जीने वाले लोगों का देश बन गया है। स्वास्थ्य विज्ञान का यह मानना है कि तनाव, कैंसर का सबसे बड़ा कारण है'

यह एक सच है कि यदि हम मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार हों तो हम नई बातें फटाफट सीख जाते हैं। एक और बड़ा सच यह है कि हमने जो सीख लिया वह ऐसा खज़ाना है कि हमेशा हमारे साथ रहता है, कोई उसे हमसे छीन नहीं सकता। सीखने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती, बुढ़ापे में भी, बशर्ते कि हम सीखने के लिए तैयार हों। हाल ही में मैंने कुछ नई बातें सीखी हैं। मैं शुरू से ही कुछ-कुछ लापरवाह और खिलंदड़ा रहा हूं। मैं उदास नहीं होता, अक्सर खुश रहता हूं, पर मैंने मन में कई ग्रंथियां पाल रखी थीं। मेरे मन में दुनिया भर के प्रति शिकायतें थीं और मैं समझता था कि दुनिया को वह समझना चाहिए जो मैं समझता हूं जबकि सच यह है कि खुद मुझे बहुत कुछ समझने की आवश्यकता थी। जीवंत जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि हम खुद से ज्यादा प्यार करना सीखें। खुद से प्यार करने का मतलब है कि हम अपनी सेहत पर फोकस करें, सच्चे रिश्ते बनाएं और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। सेहत पर फोकस में फिर तीन और नुक्ते हैं। इनमें से पहला है भोजन, दूसरा है व्यायाम और तीसरा है तनावरहित खुशी भरा मन। भोजन में ज्यादा नमक, चीनी और संस्कारित भोजन की जगह हरी सब्जियों, सलाद, दाल की प्रचुरता वाला फाइबर और प्रोटीन युक्त

ताज़ा और संतुलित भोजन हमारे स्वास्थ्य में बड़ी भूमिका निभाता है। थोड़े से योग और व्यायाम का मिलाजुला रूप शरीर के लिए आदर्श है। तनावरहित खुशी भरा मन कहने में जितना आसान दिखता है, करने में यह उतना ही कठिन है।

यह एक लंबी मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा है, पर इसकी शुरुआत हर उम्र में संभव है। मानसिक शांति और संतुलन की बहुत छोटी सी और आसान शुरुआत तो सिर्फ यहां से हो सकती है कि हम हर तीन घंटे बाद आराम से बैठ कर लंबे सांस लेने की आदत डालें और जब कभी तनाव या चिंता में हों तो बैठ जाएं और गहरे लंबे सांस लें। श्वसन की इस प्रक्रिया से तनाव दूर हो जाता है। इस तरह शरीर में ज्यादा आक्सीजन जाती है और हमारी मांसपेशियों को नया जीवन मिलता है। ऐसा ही एक और आसान तरीका है उबासी लेना। तनाव अथवा उदासी की स्थिति में यह एक रामबाण औषधि है। उबासी लेते समय आपका पूरा ध्यान उबासी की तरफ हो जाता है, शेष चिंताओं से आपका ध्यान हट जाता है और आपकी मांसपेशियों को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। हम में से बहुत से लोगों को अक्सर रात में नींद न आने की समस्या से गुजरना पड़ता है। जब कभी अनिद्रा की शिकायत हो, कुछ पढने लग जाएं या किसी गतिविधि में व्यस्त हो जाएं। महिलाओं के लिए बर्तन साफ करना, उन्हें करीने से सजाना एक आसान उपाय है।

सच तो यह है कि हम पुरुष भी इसे आजमा सकते हैं। इस सुझाव पर हंसें नहीं, आजमाएं, और आप पायेंगे कि यह जादू की तरह काम करता है और जल्दी ही आप महसूस करते हैं कि आप नींद के लिए तैयार हैं। जी भर के जीने की यह साधारण सी दिखने वाली कलाएं असल में बहुत असाधारण हैं। तनाव रहित जीवन जीने और खुश रहने में हमारी मानसिकता की भूमिका बहुत ज्यादा है। अपनी आदतें बदलना एक लंबी यात्रा हो सकती है, थोड़ी सी कठिन हो सकती है, पर कुछ ही अभ्यास से हम ऐसा कर सकते हैं। दरअसल यह 'करने' और 'होने' का फर्क है, यह 'डूइंग' और 'बीइंग' का फर्क है। एक उदाहरण से मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा। शुरू-शुरू में जब मैं 'खुश रहने और खुश रखने की कला' पर वर्कशाप संचालित किया करता था तो मैं वर्कशाप के प्रतिभागियों को डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध पुस्तक 'लोक व्यवहार' (हाउ टु मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल) भी बांटा करता था। एक बार मेरी वर्कशाप में एक ग्रामीण दंपत्ति भी भाग ले रहे थे। रुटीन के मुताबिक वह पुस्तक मैंने उन्हें भी दी। कुछ दिन बाद जब उनसे दोबारा मुलाकात हुई और मैंने पूछा कि पुस्तक पढ़ी या नहीं, तो उनका उत्तर था कि 'यह किताब तो चालाकियों से भरी हुई है'।

आज जब मैं उस घटना पर विचार करता हूं तो मुझे समझ आता है कि उस ग्रामीण दंपत्ति ने कितनी सरलता से एक बहुत बड़े सच का खुलासा किया था। यदि हम किसी को पसंद नहीं करते, और उसकी प्रशंसा करते हैं तो हम काम तो अच्छा कर रहे हैं, पर हम खुद अच्छे नहीं बन पाये हैं। इससे हमारे मन-मस्तिष्क में तनाव रहता है, जो कई रोगों का कारण बनता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (वल्र्ड हैल्थ आर्गेनाइज़ेशन) ने एक एडवाइज़री जारी करके बताया है कि अगले 8 सालों में, यानी सन् 2025 तक 87 फीसदी भारतीय कैंसर के मरीज़ हो जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि भारत में बिकने वाला 68.7 प्रतिशत दूध सिंथैटिक या मिलावटी होता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चिकित्सकों की दृष्टि से देखें तो यह एक सच्चाई है ही, पर जरा और गहराई में जाएं तो हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। हमारा देश इस समय झगड़ालू प्रवृत्ति और मानसिक तनाव में जीने वाले लोगों का देश बन गया है।

स्वास्थ्य विज्ञान का यह मानना है कि तनाव, कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, जबकि अध्यात्म का मानना है कि कैंसर का एकमात्र कारण तनाव ही है। हमें बीमार करने वाले जितने भी कारण हों, चाहे वह वायरस है या गलत खानपान या खराब जीवन शैली, हमारा शरीर उनसे निबट सकता है, पर तनाव एक ऐसा रोग है जिसकी कोई काट नहीं है और इसके परिणामस्वरूप शरीर अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। लब्बोलुबाब यह कि हम खुद से प्यार करें। स्वास्थ्यवर्धक भोजन लें, व्यायाम के लिए समय निकालें, किसी की प्रशंसा करने से पहले उसकी अच्छाइयों की तरफ ध्यान दें, अपने मन में उसके लिए प्रेम जगाएं, फिर हमें झूठी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं रहेगी और अपने मन में कोई तनाव भी नहीं रहेगा। इससे सच्चे रिश्ते बनेंगे जो जीवन भर हमारा साथ देंगे। गहरे लंबे सांस, उबासी और किसी गतिविधि में व्यस्तता के साथ अपने बाकी जीवन में परिवर्तन लाएं ताकि जब तक जीवित रहें, जीवंत रहें। जी भर के जीने के लिए अपने को हमेशा सकारात्मक रखें। इसी से आदमी को सफलता मिलती है और सफलता हमेशा खुशियां लेकर आती है। सकारात्मक सोच जीवंतता है।

संपादक की कलम से

मध्यम वर्ग का बजट

इस साल एक फरवरी का दिन बेहद महत्त्वपूर्ण रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का 10वां और मौजूदा कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट संसद में पेश किया। अब 2024 में आम चुनाव के जनादेश के बाद ही अगला संपूर्ण बजट पेश किया जा सकता है। फिलहाल बजट से देश के नौकरीपेशा, मेहनतकश और मध्यम वर्ग गदगद हो सकते हैं। उसका विश्लेषण आगे करेंगे, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की हकीकत 'आर्थिक सर्वेक्षण' और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आकलन से स्पष्ट है कि 2023-24 में जीडीपी की विकास दर 6-6.8 फीसदी के बीच रहेगी। आईएमएफ ने भी हमारी विकास दर 6.1 फीसदी आंकते हुए आकलन किया है कि भारत विश्व में सबसे तेज़ बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। 'आर्थिक सर्वेक्षण' में चालू वित्त वर्ष की विकास दर 7 फीसदी अनुमानित है। अर्थशास्त्रियों के विश्लेषण हैं कि यदि बीते चार साल का हिसाब देखा जाए, तो जीडीपी में बढ़ोतरी 3.2 फीसदी सालाना की दर से हुई है।

चिंतित तथ्य यह है कि 2019-20 में, कोरोना महामारी से पहले, भी विकास दर 3.7 फीसदी थी। बजट को समझने से पहले यह जानना अनिवार्य है कि महंगाई दर 6.8 फीसदी और बेरोजगारी दर 7.2 फीसदी रही। यानी तय हदबंदियों से अधिक है। 'नेशनल करियर सर्विस पोर्टल' से स्पष्ट है कि जनवरी, 2023 तक 2.75 करोड़ से अधिक बेरोजगारों को नौकरी चाहिए। यह आंकड़ा 3.5 करोड़ भी बताया जाता है। बहरहाल महंगाई, बेरोजगारी, कम उत्पादन, कम निर्यात, कृषि और गरीबी आदि गंभीर चुनौतियां हैं, जिन्हें बजट में संबोधित किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने 5वें बजट में सबसे बड़ी, उत्पादक, समावेशी, प्रगतिशील और मेहनतकश, नौकरीपेशा वर्ग से जुड़ी यह घोषणा की है कि अब 7 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा। इस दायरे को एकदम 2 लाख रुपए बढ़ाया गया है।

आम करदाता को 33,800 रुपए का सीधा फायदा होगा। इसी के मद्देनजर माना जा रहा है कि यह 45 करोड़ लोगों के मध्यम वर्ग का बजट है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे एक और ताकतवर वर्ग माना है, लेकिन तथ्य यह भी है कि देश में 8 करोड़ से कुछ ज्यादा लोग ही आयकर रिटर्न भरते हैं, लेकिन औसतन 1.5 से 2 करोड़ भारतीय ही आयकर का भुगतान करते हैं। लिहाजा इसका व्यापक असर नहीं होगा, क्योंकि 98 फीसदी नागरिक पहले भी आयकर नहीं देते थे और अब तो कर का दायरा ही बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। इस व्यवस्था का देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ सकता है, क्योंकि मध्यम वर्ग की परिधि में बड़ी आबादी आती है, बेशक वह करदाता नहीं है, लेकिन वह उपभोक्ता जरूर है, लिहाजा आम मांग और खपत बढ़ेगी। क्रयशक्ति में विस्तार होगा। जीएसटी संग्रह भी बढ़ेगा और अंततः अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। दरअसल बजट का फोकस किसान, कृषि, गरीब, सूक्ष्म-लघु उद्योग, युवा शक्ति, स्टार्टअप, महिलाओं आदि पर ज्यादा रहा है। किसानों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की ऋण योजना तैयार की गई है, तो प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों की आर्थिक मदद और प्रोत्साहन, सूक्ष्म-लघु उद्योगों के लिए 2 लाख करोड़ के अतिरिक्त व्यय का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर बजट अच्छा और समावेशी है। एकदम चुनावी और लोकलुभावन नहीं है।

इतिहास में आज

03 फरवरी का इतिहास

3 फरवरी का दिन भी भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण दिन रहा है, क्योंकि इस दिन 1945 में भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन सेवा मुम्बई से कुर्ला के बीच शुरु की गई। यही नहीं 3 फरवरी की तारीख, भारतीय नौसेना के पहले आईएनएस चक्र को भारतीय सेना में शामिल करने की भी ग्वाह बनी।

इसके अलावा इस दिन कई ऐसी घटनाएं घटी, जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गईं। 3 फरवरी के दिन कई महान शख्सियत ने भी जन्म लिया और इसी दिन कई दिग्गज लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए। आइए जानते हैं 3 फरवरी के दिन देश और दुनिया के इतिहास के बारे में –

पुर्तग़ाली तथा उस्मानों के बीच 1503 में दीव की लड़ाई भारत के दीव (अब एक केन्द्र शासित प्रदेश) में हुई।

सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना ने उदगीर के युद्ध में निजाम को 1760 में बुरी तरह हराया।

विश्व में 1815 में पनीर उत्पादन का पहला कारखाना स्विटजरलैंड में खोला गया।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 3 फरवरी, 1915 को स्वेज नहर पर जर्मनी और उसमानी शासन की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर हमला किया। आपको बता दें कि स्वेज नहर उस समय ब्रिटेन के नियंत्रण में थी।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की शुरुआत 1916 में हुयी।

मुम्बई से कुर्ला के बीच भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन सेवा 1925 में शुरू।

पहली बार हवाई जहाजों से पार्सल भेजने का सिलसिला 1934 में शुरू हुआ।

जावा पर 1942 में पहला जापानी हवाई हमला हुआ।

जर्मनी और पूर्व सोवियत संघ के बीच स्टालिनग्राड नामक रक्तरंजित युद्ध 3 फरवरी साल 1943 में खत्म हुआ।

रूस 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ शामिल होने पर सहमत हुआ।

प्रयाग में 1954 में हुए कुंभ मेले के दौरान मची भगदड़ में लगभग 500 से अधिक लोगों की जान गयी।

बेनेलक्स आर्थिक संघ का गठन 3 फरवरी, 1958 को हुआ।

3 फरवरी, साल 1969 के दिन रुस का चालक रहित अंतरिक्ष यान लूना 9 चंद्रमा पर पहली बार पूरी तरह कंट्रोल में रहते हुए उतरा।

भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र की 1970 में तलचर में आधारशिला रखी गई।

सन 1972 में जापान के सप्पारो में एशिया में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया।

भारतीय नौसेना की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी "आईएनएस चक्र"को 1988 में सैन्य बेड़े में शामिल किया गया।

अंतरिक्षयात्री आईलीन कॉलिन्स 3 फरवरी साल 1995 को अंतरिक्ष शटल को संचालित करने वाली पहली बनीं।

भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में 1999 में डेमोक्रेटिक जनता दल का पुनरुद्धार हुआ।

विश्व आर्थिक मंच की 29 वीं वार्षिक बैठक का 3 फरवरी साल 1999 में स्विजरलैंड के दावोस में समापन हुआ।

आतंकवाद के खिलाफ, भारत ने उजबेकिस्तान के साथ मिलकर 3 फरवरी, 2003 के दिन ही संयुक्त कार्यदल का गठन किया था।

कुर्सी को जिंदा रखने की एक विनय

साहिबो, हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि न चाहते हुए भी हमें अपनी कुर्सी को जिंदा रखने के लिए, अपनी टोपी को ऊंचा रखने के लिए आपके सामने हर बार चुनावों का बिगुल बजाने के बाद वायदों की बारात सजानी पड़ती है। पिछली बार बारात सजाई थी तो आप सब के लिए 'अच्छे दिन आने' का उपहार देने का वायदा किया था। आपने उम्मीदों के कनकौए उड़ाते हुए हमें विजय का आसमान भेंट कर दिया। इसके बाद हमने इनके हर भाषण का करतल ध्वनि से स्वागत करते हुए न जाने कितने पत्थर तबीयत से उछाले हमारे आसमान में कोई सुराख नहीं हो सका। हमने कवि दुष्यन्त के शे'यर के सार्थक न हो पाने की त्रासदी झेलते हुए अपने इर्द-गिर्द घिरते हुए बेकारी, बीमारी, गरीबी और कज़र्दारी के आसमान को अपना जान गले से लगा रहने दिया। अच्छे दिन आने की उम्मीद हमारे क्षितिज पर एक इन्द्रधनुष बनकर उभरी थी। लेकिन भ्रष्टाचार के अजगरों ने उस क्षितिज को निगल लिया, हम अपना टूटा हुआ इन्द्रधनुष कहां तलाशने जाते? लेकिन सुखद भविष्य के सपनों की बारात फिर सजने लगी। वायदों की तश्तरियों पर चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात के चिलगोज़े तो हमारी गलियों में तशरीफ लाए, नहीं आई तो वह क्षमा प्रार्थना नहीं आई, कि हम आपके लिए अच्छे दिनों का उपहार नहीं ला पाये।

कतार में खड़ा आखिरी आदमी वहीं खड़ा-खड़ा प्रस्तर हो गया ताकि उनसे उतना भी न पूछ सके कि 'क्या हुआ तेरा वायदा'। वायदे पूरे होने का, भ्रम लेकर 'गिली गिली पाशा' कहते हुए आंकड़ों के जादूगर हमारी गलियों में तशरीफ अवश्य लाए थे। उन्होंने अपनी तरक्की के सूचकांकों के आधारवर्ष बदल दिए, गणना प्रक्रिया बदल दी, लेकिन उनकी जादूगर मैण्ड्रैक्स जैसी लम्बी जादुई टोपी में से कोई तरक्की और खुशहाली का खरगोश न निकला। गज़ब खुदा का किसान अपने खेतों में भरपूर फसल उगाने के बावजूद फसल खरीदने और बेचने वाली रोगी मण्डियों के बाहर चौराहों पर फंदा लेकर अपने जीवन का अन्त करते रहे, और समय के शाहसवार उन्हें अपच का शिकार या किसी असाध्य रोगी से दुःखी होकर मर गया, बताते रहे। आंकड़ों के जादूगरों ने उनकी मौतों के रोजनामचे बन्द कर दिये, क्योंकि यह सूची सुरसा की आंत की तरह लम्बी होती जा रही थी, और इससे पीड़ित परिवारों को मुआवज़ा देने की घोषणाएं शर्मिन्दा हो रही थीं।

इन घोषणाओं ने कोई क्षमा प्रार्थना न की, हां वे रोजनामचे बंद कर दिये गये 'कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी'। जब अपनी गरीबी से जर्जर किसानों की मौतें बीमारी और गृह-कलह के खाते में चली गयीं तो खाली खजाना भला उनसे क्षमा प्रार्थना के लिए आगे क्यों आता? फिर यह वक्त क्षमा प्रार्थना का नहीं था। फिर चुनावी बिगुल बज गया, फिर गद्दी संभाले रहने की अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र माहौल पर तारी हो गई। अब ऐसा वक्त अपनी अक्षमता और असफलता के लिए क्षमा प्रार्थना का नहीं, चुनावी अखाड़े में कूद कर अपने भुजदंड फडक़ाने का होता है। भुजदण्ड फडक़ते हैं, जब उसी चौराहे पर नये तोरणद्वार सजते हैं। चौराहा तो बदहाली से और भी पहाड़-सा हो गया है। वक्त क्षमा प्रार्थना का नहीं, इस चौराहे में से एक नई उम्मीदों भरी सुबह सी, वायदों की एक और बारात लेकर निकल जाने का था। ऐसे सजानी थी यह बारात कि बाद में उसे एक विजययात्रा में तबदील करते हुए देर न लगे।

सुरेश सेठ

उच्च शिक्षा का हो पेशेवर प्रबंध

उच्च शिक्षा ऐसी हो कि छात्र भविष्य के जीवन के लिए तैयार हो सकें। इसलिए अध्यापन का कार्य भविष्य को ध्यान में रखकर हो। बेहतर हो कि उच्च शिक्षा को किसी नौकरी के लिए डिग्री हासिल करने का माध्यम मात्र न माना जाए, बल्कि इसे व्यक्ति की पूर्ण क्षमता विकसित करने का जरिया समझा जाना चाहिए। छात्रों की क्षमताओं का विकास जरूर होना चाहिए। स्कूली शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग में तालमेल जरूर होना चाहिए' ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों का कुल नामांकन प्रतिशत 2014-15 से 2020-21 तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है जिसमें एसटी छात्रों ने लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। इसके मुताबिक उच्च शिक्षा में नामांकन 4 करोड़ से पार कर गया है। किस तरीके से उच्च शिक्षा में छात्रों के प्रवेश को और गति दी जा सकती है, इस विषय को बारीकी से स्टडी करने की जरूरत है। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली पहले चुनिंदा लोगों की जरूरतें पूरी करने के मकसद से तैयार की गई थी। अब उसे ज्यादा लोगों के काम लायक बनाने के लिए बदलाव किया जाना चाहिए। इस समय उच्च शिक्षा में अभी करीब 3.5 करोड़ छात्र-छात्राओं ने दाखिला ले रखा है। इनमें 1.96 करोड़ छात्र और 1.89 करोड़ छात्राएं हैं। यानी कुल एनरोलमेंट का 49 फीसदी छात्राएं हैं। साल 2025 तक उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाले सबसे अधिक छात्र और छात्राएं भारत में ही होंगे। 2030 तक उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले सबसे अधिक युवा भारत में होंगे। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी होने के बावजूद इसे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये चुनौतियां पठन-पाठन की गुणवत्ता, सरकारी-निजी भागीदारी, विदेशी संस्थानों का प्रवेश, रिसर्च क्षमता में वृद्धि और फंडिंग, इनोवेशन, अंतरराष्ट्रीयकरण, वैश्विक अर्थव्यवस्था की बदलती मांग जैसे क्षेत्रों में हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए बीते दो दशकों में अनेक प्रयास हुए हैं, लेकिन नई चुनौतियां भी लगातार उभर रही हैं। छात्र जो शिक्षा ग्रहण करते हैं और रोजगार के लिए उन्हें जिस कौशल की जरूरत होती है, उनमें भी बड़ा अंतर होता है। इसकी प्रमुख वजह उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता की कमी भी है। इसके अलावा पाठ्यक्रम में कौशल विकास का न होना भी एक कारण है। हमें उच्च शिक्षा के संदर्भ में रिसर्च और अध्यापन को अलग करने के लिए अनेक प्रयासों की जरूरत है।

बदलते समय के साथ लचीले पाठ्यक्रम की भी आवश्यकता है। पाठ्यक्रम तय करने और कौशल विकास में छात्र को काम देने वाले की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा अंतर-विषयी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कारगर अध्यापन की कमी, पुराने पड़ चुके पाठ्यक्रम और पुरानी शिक्षण विधि ने प्रशिक्षित फैकल्टी की कमी की समस्या को और बढ़ाया ही है। छात्रों को विभिन्न तरह की स्किल विकसित करने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। इनमें एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोलैबोरेटिव वर्किंग जैसी स्किल शामिल हैं। इनकी पढ़ाई और इनका मूल्यांकन इस तरह हो कि छात्रों को रटना न पड़े। बहु-विषयी रिसर्च के अवसर न होने के कारण विज्ञान और समाजशास्त्र, दोनों में क्वालिटी रिसर्च की कमी है। इससे उद्योगों के साथ जुड़ाव प्रभावित हुआ है। उच्च शिक्षा में पेशेवर मैनेजमेंट के जरिए उत्कृष्टता हासिल करने के लिए नए गवर्नेंस मॉडल की आवश्यकता है जिसमें पारदर्शिता, समानता, जवाबदेही और समावेशिता जैसी विशेषताओं को शामिल किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा संस्थानों को विकेंद्रीकृत गवर्नेंस की दिशा में भी कदम बढ़ाना चाहिए ताकि कामकाज के विभिन्न स्तरों पर स्वायत्तता, जवाबदेही, लचीलापन, विश्वास और पारदर्शिता कायम हो सके। भावी जरूरतें पूरी करने वाला विश्वविद्यालय बनाने के लिए रेगुलेटर को भी अपनी भूमिका बदलने की जरूरत है। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के साथ शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण को देखते हुए उच्च शिक्षा संस्थानों को पारंपरिक विश्वविद्यालय प्रशासन का तरीका छोडऩा चाहिए जो 19वीं सदी की जरूरतों पर आधारित है।

पोक्सो एक्ट पर पुनर्विचार की दरकार

हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से बाल आश्रमों में रह रहे अनाथ बालक-बालिकाओं के प्रति संजीदगी एवं संवेदनाएं दिखाई हैं, वह काबिले-तारीफ है। इससे बाल सुरक्षा को बल मिलेगा। बच्चों की सुरक्षा हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी एवं कत्र्तव्य है। अध्यापकों, अभिभावकों, महिला मंडलों, पंचायतों, यूथ क्लबों, संस्थानों को मिलकर बाल हितैषी समाज की संरचना करनी है'

'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट' (पोक्सो) 2012 में लाया गया था। यह कानून 18 साल से कम उम्र के लडक़े और लड़कियों पर समान रूप से लागू होता है। समझ लीजिए कि इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है और उनके साथ यौन उत्पीडऩ को अपराध माना गया है। संशोधित कानून में 12 वर्ष से कम उम्र वाली बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद आरोपी को फांसी की सजा का प्रावधान है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि न्यायपालिका को पोक्सो एक्ट के तहत सहमति की उम्र को लेकर चल रही बहस पर ध्यान देना चाहिए। पोक्सो एक्ट 18 वर्ष से कम उम्र वालों के मध्य यौन-संलिप्तता को आपराधिक मानता है, यह देखे बिना की नाबालिगों के बीच सहमति थी या नहीं। क्योंकि कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र वालों के बीच सहमति मान्य नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने इस श्रेणी के केस देखे हैं तथा वे जजों के सामने कई सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने युवा हेल्थ केयर सेक्टर के विशेषज्ञों की रिसर्च को आधार बनाने का सुझाव दिया। गौरतलब है कि डी. वाई. चंद्रचूड़ ने वर्ष 2018 में अपने पिता पूर्व न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ के 33 साल पुराने फैसले को पलट दिया था। दरअसल जस्टिस वाई. वी. चंद्रचूड़ ने 1985 में व्यभिचार की धारा 497 को कायम रखते हुए कहा था कि यह असंवैधानिक नहीं है। जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने 2018 में शादीशुदा स्त्री एवं पुरुष को स्वेच्छा के आधार पर शादी से बाहर संबंध की छूट को मान्यता देते हुए इसे संवैधानिक बताया तथा व्यापार की धारा 497 को रद्द किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि पोक्सो एक्ट-2012 प्रेम में पड़े किसी टीनएजर को सजा देने के लिए नहीं है। मामला एक 16 वर्षीय टीनएजर का है जिस पर बलात्कार का केस चल रहा था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस को खारिज किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपी नाबालिग के हित में फैसला सुनाते हुए कहा कि पोक्सो एक्ट क्यों लाया गया था। हमें यह भूलना नहीं चाहिए, लेकिन इस का अर्थ यह नहीं है कि इसका उपयोग हम उन टीनएजर को सजा देने हेतु करें जोकि प्रेमवश ऐसे कामों को कर बैठते हैं जो कि एक्ट में अपराध हैं। जस्टिस एम नागाप्रसन्ना ने कहा कि हर मामला जो कि यौन प्रसंग (सेक्सुअल एक्टिविटी) से जुड़ा है, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत नहीं आ सकता। निःसंदेह पोक्सो एक्ट का उद्देश्य नाबालिग बच्चों के यौन उत्पीडऩ को सजा के माध्यम से रोकना है। समाज में प्रतिदिन हमें नाबालिगों के यौन प्रताडऩा व शोषण की खबरें विचलित करती हैं। पोक्सो एक्ट के तहत फॉरेंसिक लैब धर्मशाला के अध्ययन में खुलासा हो चुका है कि प्रदेश की बेटियां अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। प्रदेश के बाल आश्रमों में भी बेटियों के उत्पीडऩ के मामले समाचार पत्रों की सुर्खियां बन चुके हैं। 2017 में चंबा में छात्राओं ने आश्रम के तीन कर्मचारियों पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे।

इससे पूर्व 2002 में भी आश्रम के एक कर्मचारी ने छात्रा को हवस का शिकार बनाया था। जिला कांगड़ा के गरली में प्रताडऩा का शिकार हो रही बालिकाओं ने बाल कल्याण समिति में छेड़छाड़ के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई थी। दिसंबर 2021 में चेन्नई में एक नाबालिग लडक़ी जोकि 11वीं कक्षा की छात्रा थी, ने यौन उत्पीडऩ से तंग आकर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। उसका सुसाइड नोट बेहद भावुक तथाकथित समाज को आईना दिखाने वाला था : 'स्टॉप सेक्सुअल हरासमेंट, न तो शिक्षकों पर भरोसा करो न ही रिश्तेदारों पर'.लड़कियों के लिए तो बस मां की कोख और कब्र ही सुरक्षित रह गई है।' स्पष्ट रूप से पोक्सो एक्ट के तहत सोलन व शिमला में दुराचारी कलयुगी बाप, नाहन में फूफा, बिलासपुर में चाचा, निरमंड में भांजा व दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। आवश्यक है कि पोक्सो एक्ट को अधिक व्यावहारिक बनाया जाए तथा विद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थानों में यौन हिंसा से बचाने के लिए बेटियों के साथ-साथ लडक़ों को भी जागरूक किया जाए। हम यह सच अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि बाल और यौन शोषण में आधे से ज्यादा दुष्कर्म पीड़ित लडक़े हैं। बच्चों को सेफ अनसेफ टच के बीच फर्क बताना आवश्यक है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि आरोपी और पीड़िता के बीच स्किन-टू-स्किन का सीधा संपर्क नहीं हुआ है तो पोक्सो एक्ट के अधीन यौन उत्पीडऩ का कोई अपराध नहीं बनता है।

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि टच के अर्थ को स्किन-टू-स्किन तक सीमित करने से पोक्सो कानून की बेहद संकीर्ण और बेहूदा व्याख्या निकलकर आएगी तथा इससे इस कानून का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कपड़ों के ऊपर से भी बच्चों को गलत नीयत से छूना भी पोक्सो एक्ट में आता है।

ब्रीफ न्यूज

विकसित देश बनना है तो शिक्षा पर देना होगा ध्यान

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 2023-24 का बजट पेश किया। यह बेहद सूझबूझ वाला और संतुलित बजट है। विप्रो के चेयरमैन रिशाद प्रेमजी का कहना है कि सरकार ने बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर में इनवेस्टमेंट, ग्रीन ग्रोथ, युवाओं में कौशल विकास पर जोर दिया गया है। भारत के विकसित देश बनना है तो उसके लिए एजुकेशन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भारत दुनिया के उन गिने-चुने देशों में शामिल है, जिसने पिछले तीन सालों में कई झटकों को डटकर सामना किया है। वित्त वर्ष 2023 में इसकी आर्थिक विकास दर (GDP ग्रोथ) 7 फीसदी के करीब रहने का अनुमान है। जो कि विश्व की बड़ी इकॉनमी में सबसे तेज ग्रोथ है। लेकिन क्या यह आने वाले वक्त में भी मजबूत ग्रोथ दिखाएगा और मजबूती से डटा रहेगा? इसके साथ एक सवाल यह भी है कि क्या भारत 2047 तक विकसित देश बनने का अपना वादा पूरा कर पाएगा? इस विजन को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेहद सूझबूझ वाला और संतुलित बजट पेश किया है। इस बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भारी निवेश, ग्रीन ग्रोथ, युवाओं में कौशल विकास का खयाल रखा गया है। वित्त मंत्री ने बजट में जिस समावेशी विकास यानी इन्क्लूसिव ग्रोथ की बात कही है, उसके बारे में एक बड़ा सच यही है कि टेक्नॉलजी की उसमें बड़ी भूमिका होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नॉलजी सेक्टर से देश को सालाना 250 अरब डॉलर की आमदनी मिलती है और इसमें 50 लाख लोग काम करते हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि इन 50 लाख लोगों में से 36 फीसदी महिलाएं हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नॉलजी सेक्टर ने जो यह मुकाम हासिल किया है, सवाल यह है कि उसे संजोते हुए कैसे आगे बढ़ाया जाए?

इसमें भारत में बड़ी युवा कामकाजी आबादी से मदद मिल सकती है। हम एक ग्लोबलाइज्ड लेबर मार्केट तैयार कर सकते हैं। माना जा रहा है कि साल 2030 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स बन चुका होगा। तब हमारी 60 फीसदी से अधिक आबादी काम करने योग्य होगी। जब दुनिया के कई देश बूढ़े हो रहे हैं, उसमें भारत के हक में यह एक बड़ा पॉजिटिव होगा। इसका फायदा उठाने के लिए देश को मौजूदा कामगारों को बेहतर स्किल की जरूरत है। उन्हें ऐसी नॉलेज से लैस होना होगा, जिससे वे पूरी दुनिया में कहीं भी काम करने के योग्य हों।

नहीं मिल रहे पेशेवर

आज देश की इंफॉर्मेशन टेक्नॉलजी इंडस्ट्री को कई क्षेत्रों में बेहतर पेशेवर नहीं मिल रहे हैं। इनमें रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा और एनालिटिक्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए इंडस्ट्री, एकेडेमिक जगह और सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है और उसके लिए एक व्यापक योजना बनानी होगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में सरकार ने लाखों युवाओं को ऑन जॉब ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया है। इसके लिए इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम किया जाएगा। इस योजना में कोडिंग, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नलॉजी को शामिल किया गया है, जिसके लिए मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं।

बजट में सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर काफी जोर दिया है। वह जीडीपी का 3.3 फीसदी निवेश इसमें करने जा रही है। इससे भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नॉलजी सेक्टर को भी फायदा होगा। अच्छी सड़कें, बिजली, क्वॉलिटी हाउसिंग, बेहतर रेल और एविएशन कनेक्टिविटी से छोटे शहरों को भी विकास में साझेदार बनाया जा सकेगा। हमारे बड़े शहरों में घनी आबादी रहती है और वहां कई सुविधाओं और सेवाओं को और बेहतर बनाने की जरूरत है। लंबे समय से देश में लोग वैसी जगहों पर जाने को मजबूर रहे हैं, जहां रोजगार हैं। अब हमें उन जगहों पर रोजगार को ले जाना होगा, जहां लोग रहते हैं, जहां के वे बाशिंदे हैं।

समावेशी विकास पर जोर

वित्त मंत्री ने बजट में समावेशी विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने आर्थिक विकास का फायदा देश के सभी वर्गों तक पहुंचाने की बात कही। इसके लिए एक समान, हाई क्वॉलिटी एजुकेशन और हेल्थकेयर तक हर देशवासी की पहुंच होनी चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि बच्चों में तार्किक सोच पनपे। उन्हें मुश्किलों का हल तलाशने, लीडरशिप और बेहतर कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए। यह तभी हो सकता है, जब शिक्षक भी अच्छे हों। हमें इसके लिए एकेडमिक और प्रशासन की मदद चाहिए होगी। यह भी पक्का करना होगा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में संसाधनों की कमी बाधा न बने। नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का लक्ष्य भी यही है।

गरीबी से सिर्फ एक मेडिकल बिल दूर हैं आप... सीतारमण ने चला दिया है सेविंग की सोच पर हथौड़ा!

क्या सरकार बचत के बजाय खर्च को प्रोत्साहित करना चाहती है? मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट इसी ओर इशारा करता है। इसमें पूरा फोकस बिना छूट वाली इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को लुभावना बनाने पर है। वहीं, सेविंग को प्रमोट करने वाली पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था को यह बजट पूरी तरह नजरअंदाज करता है।

नईदिल्ली: बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ने का ऐलान होते ही शेयर बाजार उछल गया। जैसे ही उसे 'असलियत' का एहसास हुआ उसकी हंसी गायब होने लगी। शेयर बाजार शरीर में दिल की तरह है। हर हरकत पर उसकी धड़कनें तेज और धीमी होती हैं। वह बिना प्रतिक्रिया दिए रह ही नहीं सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। इसमें उन्होंने इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को आकर्षक बनाने का जुगाड़ किया। इसका ऐलान वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में हुआ था। दो साल पहले लाई गई इस व्यवस्था को फीकी प्रतिक्रिया मिली। ज्यादातर लोगों ने बिना डिडक्शन और एक्जेम्पशन वाली व्यवस्था में जाने के बजाय इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था में रहने का फैसला किया। इसमें उन्हें सेविंग पर टैक्स से छूट मिलती है। भारतीय सेविंग को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। इसका फायदा भी हुआ है। न सिर्फ लोगों को, बल्कि सरकार को भी। इसने मुश्किल समय में अर्थव्यवस्था का दिवाला निकलने से बचाया है। जब मंदी ने पूरी दुनिया पर गाज गिराई भारत चट्टान की तरह खड़ा रहा। लोगों की छोटी बचत ने मंदी के तूफान में भी देश की अर्थव्यवस्था पर आंच नहीं आने दी। हालांकि, सीतारमण के ताजा बजट ने बचत की सोच पर हथौड़ा चला दिया है। सरकार 'बचत' को हतोत्साहित करने वाली इनकम टैक्स की नई व्यवस्था की तरफ लोगों को ले जाना चाहती है। वहीं, सच यह है कि यही बचत लोगों को गरीब होने से बचाती है। वरना जिस तरह दवा-पानी का खर्च बढ़ा है, उसमें सिर्फ एक बार अस्पताल में भर्ती होना किसी को गरीब बनाने के लिए काफी है।

बिना पुश किए कोई नहीं खरीदता इनवेस्टमेंट प्रोडक्ट

वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत पर्सनल इनकम टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाया है। इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया है। यानी किसी की इनकम 7 लाख रुपये तक है तो उसे टैक्स नहीं देना होगा। अभी तक यह लिमिट 5 लाख रुपये थी। इसके अलावा टैक्स स्लैब को सात से घटाकर पांच किया गया है। बेशक, इनकम टैक्स की नई व्यवस्था कम्प्लायंस के लिहाज से अच्छी है। लेकिन, यह सेविंग को प्रोत्साहित नहीं करती है। इस व्यवस्था में टैक्स के रेट कम हैं। लेकिन, इसमें तमाम तरह के एक्जेम्पशन और डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है। एक्जेम्पशन और डिडक्शन बेनिफिट पाने के लिए ही लोग अब तक इनवेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में निवेश करते रहे हैं।

फिलिप कैपिटल में एडवाइजर प्रतीक मिश्रा कहते हैं कि आज भी देश में लोगों को इनवेस्टमेंट प्रोडक्ट खरीदने के लिए पुश करना पड़ता है। बहुत कम लोग हैं जो अपने आप इंश्योरेंस और सिप शुरू करते हैं। इसका कारण है कि स्कूलों और कॉलेजों में फाइनेंशियल लिट्रेसी पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत कम जानते हैं। टैक्स बचत के लिए ही ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड की ईएलएसएस जैसी स्कीमों में निवेश करते थे। अपने और सीनियर सिटीजन पैरेंट्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी भी लोग उसके बेनिफिट्स के कारण कम टैक्स बचत के लिए ज्यादा खरीदते थे। इस लिहाज से बजट 2023 सेविंग पर हथौड़ा मारता है।

पूरा फोकस नई इनकम टैक्स व्यवस्था को लुभावना बनाने पर

वित्त मंत्री ने बिना छूट वाली नई टैक्स व्यवस्था को लुभावना बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत इनकम टैक्स लिमिट तो बढ़ाई ही गई है, इसे 'डिफॉल्ट' बनाने का प्रस्ताव भी किया गया है। 'डिफॉल्ट' से मतलब यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपने ऑप्शन नहीं चुना तो खुद ही आप नई इनकम टैक्स व्यवस्था में मूव कर जाएंगे। इस तरह सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था को बड़ा पुश दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह केवल उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद है, जो कोई सेविंग नहीं करते हैं। वहीं, बचत को बढ़ावा देने वाली इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था को जस का तस रखा गया है। इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये की इनकम पर जीरो इनकम टैक्स लगेगा। 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की इनकम पर पांच फीसदी, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये की इनकम पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। जहां तक नई टैक्स व्यवस्था का सवाल है तो इनकम टैक्स स्लैब के तहत 3 लाख रुपये तक की आय पर को ई टैक्स न हीं लगेगा। 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये पर 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपये पर 10 फीसदी, 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 15 फीसदी, 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।

क्या बचत के बजाय खर्च को प्रोत्साहित करना चाहती है सरकार?

साफ है कि सरकार का झुकाव नई इनकम टैक्स व्यवस्था की ओर है। यह फाइनेंशियल प्रोडक्ट में निवेश करने पर मिलने वाली रियायतों को घटाती है। इन प्रोडक्टों में म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग स्कीमें, इंश्योरेंस प्रीमियम पर खर्च इत्यादि शामिल हैं। होम लोन के ब्याज का पेमेंट करने वालों को भी फायदा नहीं होगा। भारतीय बचत को कितनी तवज्जो देते हैं, उसे म्यूचुअल फंड सिप के आंकड़ों से समझा जा सकता है। यहां सिप को सिर्फ इसलिए लिया गया है क्योंकि यह छोटी बचत का सबसे आसान तरीका है। दूसरी बात यह हैं कि हाल में इसे लेकर लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। म्यूचुअल फंड उद्योग के संगठन एम्फी के आंकड़ों की मानें तो सिर्फ दिसंबर 2022 में सिप के जरिये 13,573 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ था। वित्त वर्ष 2022-23 में 1,14,154 करोड़ रुपये सिप के जरिये निवेश किए गए। हाल के वर्षों में यह निवेश लगातार बढ़ा है। यह पैसा इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट में लगता है। इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर बाजार किसी भी आंधी में खड़े रहते हैं। जब विदेशी निवेशक (एफआईआई) पैसा निकालते हैं तो घरेलू बचत के जरिये निवेश का यही पैसा अर्थव्यवस्था को संभालता है। यह और बात है कि बजट 2023-24 में सरकार ने इस बात को नजरअंदाज किया है। बजट 2023-24 बचत के बजाय खर्च को प्रोत्साहित करने वाला है।

डिजीलॉकर को बनाया जाएगा और आसान, मिलेंगी ये कई सुविधाएं, डॉक्यूमेंट्स लेकर चलने की जरूरत

आम बजट का इंतजार देश के सभी वर्गों को था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार यानी 1 फरवरी 2023 को आम बजट पेश किया था। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने डिजीलॉकर को लेकर भी ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बताया कि डिजीलॉकर को और आसान बनाया जाएगा। लोगों को अपने साथ दस्तावेज लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी।

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आम बजट बुधवार को पेश कर दिया है। इस बजट में कई घोषणाएं की गईं। इनमें एक ऐलान डिजीलॉकर (Digilocker) को लेकर भी किया गया। दरअसल सरकार केवाईसी (Know Your Customer) की प्रक्रिया को सरल बनाने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2003 पेश करते हुए ऐलान किया था कि डिजीलॉकर (Digilocker) का दायरा बढ़ाया जाएगा। इस प्लेटफार्म पर व्यक्तिगत रूप से सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों के लिए डिजीलॉकर की स्थापना की जाएगी। सरकार के इस फैसले से फिनटेक सेवाओं का फायदा होगा। इससे फिनटेक फर्म के खर्च को कम करने में भी मदद मिलेगी। वहीं इससे कारोबार में आसानी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के मुताबिक, आधार, पीएम जनधन योजना, वीडियो केवाईसी, इंडिया स्टैक और यूपीआई (UPI) के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भारत में फिनटेक सेवाओं को सुविधा मिलती है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजीलॉकर का दायरा इस तरह बढ़ाया जाएगा कि कंपनियों को अपने ग्राहक को जानने की औपचारिकताएं केवल एक बार पूरी करनी होंगी। इसका इस्तेमाल अन्य सेवाओं को भी सत्यापित करने के लिए भी किया जा सकता है।

डिजीलॉकर के विस्तार से लोगों को मिलेंगी कई सुविधाएं

ईटी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, एक सवाल के जवाब में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केवाईसी के लिए अब डिजीलॉकर (Digilocker) का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, उदाहरण के लिए, अगर आपने पहले ही बैंक खाता खोलने के लिए दस्तावेज़ जमा कर दिए हैं, तो आपको बीमा या नए होम लोन के लिए प्रक्रिया को दोहराने की ज़रूरत नहीं होगी। डिजीलॉकर का इस्तेमाल करके इस तरह की सुविधा बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि डिजीलॉकर एक काफी यूजफुल उपकरण है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन का एक प्रभावी हिस्सा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 2023-24 के अपने भाषण में ऐलान किया कि केवाईसी की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गैर-व्यक्तिगत डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए गैर-व्यक्तिगत सरकारी डेटा का लाभ उठाने में मदद करेगा। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि जैसे अगर हमारे पास 20 से 25 साल पहले के मौसम और जलवायु डेटा सेट है तो क्या इसका इस्तेमाल किसानों के लिए बेहतर और अधिक प्रामाणिक जलवायु पूर्वानुमान बनाने के लिए किया जा सकता है।

जानिए क्या है डिजीलॉकर

आपको बता दें कि डिजीलॉकर (Digilocker App) एक सरकारी ऐप है। इसके जरिए जो डिजिटल डॉक्यूमेंट की जानकारियां मिलती हैं वे वैलिड होती हैं। इसे बेहद सुरक्षित माना जाता है। अब सरकार ने केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, डिजीलॉकर ऐप में यूजर्स अपने सभी सरकारी या जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसे एक सॉफ्ट कॉपी ऐप भी कहा जा सकता है। डिजीलॉकर ऐप (Digilocker App) का इस्तेमाल एंड्रॉयड या आईफोन दोनों यूजर्स कर सकते हैं। इसमें आप अपना पैन कार, आधार कार्ड, 10वीं-12वीं का सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि रख सकते हैं। इसी के साथ में हार्ड कॉपी ना होने पर आप इसमें अपलोडेड दस्तावेज को सेव भी रख सकते हैं। बजट 2023 में वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि डिजीलॉकर में स्टोर आधार मान्य होगा। ऐसे में ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा मिल सकता है। बजट में ऐलान किया गया है कि साथ में हार्ड कॉपी नहीं होने पर भी डिजीलॉकर ऐप में मौजूद डॉक्यूमेंट्स मान्य होंगे। हालांकि इसके लिए मोबाइल में डिजीलॉकर ऐप होना जरूरी है।

इस तरह आप भी डिजीलॉकर में खोल सकते हैं अपना अकाउंट

डिजीलॉकर का फायदा आप भी उठा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा। यहां पर आपको डिजीलॉकर ऐप को डाउनलोड करना होगा। अब ऐप को खोलकर अपनी भाषा का चयन करें। अब नीचे स्क्रॉल करें और गेट स्टार्ट बटन पर टैप करें। अब क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। अब अपनी जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और आधार नंबर डालें। अब आपके मोबाइल नंबर और ई-मेल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपका डिजीलॉकर अकाउंट सेटअप हो जाएगा।

खजाने की फिक्र भी, ग्रोथ की राह भी

साल 2023-24 का बजट आ चुका है। इस बजट पर HUL के चेयरमैन संजीव मेहता की राय जानना चाहते हैं? यदि हां तो आपको यह आलेख पढ़ना होगा। उनका कहना है कि इस बजट में MSME से जुड़े उपाय अच्छे दिख रहे हैं।

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, वह ऐसे हालात में बनाया गया, जब दुनियाभर में माहौल अनिश्चित सा दिख रहा हे और ग्रोथ रेट घट रही है। दूसरी ओर, भारत की अर्थव्यवस्था दमदार बनी हुई है और करीब सात प्रतिशत ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। टैक्स कलेक्शन का हाल अच्छा चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर की बैलेंस शीट पर कर्ज घटा है और बैंकिंग सेक्टर में अच्छी-खासी पूंजी दिख रही है। यह आत्मविश्वास से भरी वित्त मंत्री की ओर से ऐसे देश का बजट है, जो उम्मीदों से भरा हुआ है।

इस बजट में जिस आंकड़े का सबसे ज्यादा हवाला दिया जाएगा और जिसे सबसे ज्यादा याद रखा जाएगा, वह आंकड़ा है 10 लाख करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर का। यह पिछले बजट के मुकाबले 33 प्रतिशत ज्यादा है और वित्त वर्ष 2016 के मुकाबले इसमें चार गुना बढ़ोतरी हुई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का इकॉनमी पर कई स्तरों पर असर पड़ता है। इससे प्राइवेट सेक्टर की ओर से इनवेस्टमेंट भी बढ़ेगा।

राजकोषीय अनुशासन पर भी इस बजट में ध्यान बनाए रखा गया है। वित्त वर्ष 2024 के लिए फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 5.9 प्रतिशत पर रखागया है। इस साल यह 6.4 प्रतिशत पर रहेगा, ऐसा बताया गया है। राजकोषीय अनुशासन से इस बात पर भरोसा होता है कि देश की बॉरोइंग कॉस्ट एक सीमा से बाहर नहीं जाएगी। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देने पर जोर बनाए रखा है। बजट में ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय के लिए कुल आवंटन अच्छा है। पिछले कुछ वर्षों से एमएसएमई को सपोर्ट दिया जा रहा है। इस बार के बजट में भी यही बात है। सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम के फंड में 9 हजार करोड़ रुपये डालने की बात की है। इससे एमएसएमई को और कोलैटरल फ्री कर्ज मिल सकेगा। ब्याज दर में एक प्रतिशत की कमी करने का प्रस्ताव भी किया गया है। यह सब एमएसएमई के लिए बहुत अच्छी बात है।

इस बजट में ग्रीन ग्रोथ पर बहुत जोर है। सभी सेक्टरों में टिकाऊ ग्रोथ पर फोकस किया गया है। एनर्जी ट्रांजिशन यानी प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन के बजाय पर्यावरण संरक्षण में मददगार ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अलावा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात भी है। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ये पॉजिटिव कदम हैं। भारत को इनोवेशन चेन में आगे बढ़ने की भी जरूरत है। ऐसा तभी होगा, जब सरकार और प्राइवेट रिसर्च एंड डिवेलपमेंट, शिक्षा जगत के लोग, स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटलिस्ट मिलजुलकर काम करें और इकोसिस्टम बनाएं। बजट तैयार करना एक विज्ञान भी है और कला भी। इसमें हाल-फिलहाल की जरूरतों और लंबी अवधि के लक्ष्यों, दोनों पर निगाह रखनी होती है। बजट ऐसा होना चाहिए, जो तमाम लोगों और सेक्टरों की उम्मीदें पूरी करे। इकॉनमी की बुनियाद मजबूत बनाए रखी जाए और लोकलुभावन कदमों के जाल में न फंसा जाए, ऐसा बजट होना चाहिए। वित्त मंत्री ने इस लिहाज से शानदार काम किया है।

यह बजट सेंसेक्स को 2 लाख तक ले जाने वाला है : रामदेव अग्रवाल

मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल का कहना है, निवेश के लिए प्राइवेट बैंक सबसे अच्छे दिख रहे हैं। उनका कहना है कि यह दमदार बजट है क्योंकि इसमें इंफ्लेशन को चार से पांच फीसदी के दायरे में रखने की बात है।

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, उसमें 6-7 प्रतिशत की रियल जीडीपी ग्रोथ (GDP Growth) के साथ इंफ्लेशन को 4-5 प्रतिशत के दायरे में लाने की बात है। साथ ही, फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 6 से 6.5 प्रतिशत तक रखते हुए ग्रोथ बढ़ाने के लिए सरकारी खजाने से बड़े खर्च का प्रस्ताव किया गया है। मेरी नजर में यह दमदार बजट है। सरकारी खर्च की जो क्वॉलिटी है, उसमें भी काफी सुधार दिख रहा है। बजट में टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 35 लाख करोड़ रुपये रखने की बात है। दूसरी ओर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में 30 प्रतिशत का उछाल है।

इस बजट को दमदार कहने की एक और वजह है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जितने तरह के टैक्स हैं और जो टैक्स रेट (Tax Rate) हैं, उनमें कम से कम बदलाव किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह इस सरकार का आखिरी फुल बजट था। फिर भी अच्छी बात यह रही कि वित्त मंत्री ने लोकलुभावन कदमों से परहेज किया। मैक्रो इकॉनमी की समझ रखने वाले अधिकतर विशेषज्ञ कहेंगे कि इस बजट में कैपेक्स साइकल पर सोचा-समझा दांव लगाया गया है। यानी सरकारी कैपिटल एक्सपेंडिचर से प्राइवेट सेक्टर को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए प्रेरित करना, जिससे रोजगार के ज्यादा मौके बनें और इससे लोगों की आमदनी बढ़े और वे ज्यादा खर्च करें।

इससे सरकार का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा और उसके दम पर सरकार और ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। इस तरह यह साइकल आगे बढ़ेगा।

सवाल यह है कि इन बातों का स्टॉक मार्केट के लिए क्या मतलब है? दो साल पहले बजट 2021 के आसपास सेंसेक्स 50 हजार के स्तर पर था। तब मैंने कहा था कि 10 वर्षों में सेंसेक्स 2 लाख पर जा सकता है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन इसका गणित बिल्कुल साफ है। 11-12 प्रतिशत नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के दम पर कॉरपोरेट सेक्टर की सेल्स करीब 15 प्रतिशत की दर से बढ़नी चाहिए। अगर प्रॉफिट मार्जिन ठीक रहे तो कंपनियों का मुनाफा भी 15 प्रतिशत बढ़ना चाहिए। स्टॉक मार्केट चूंकि मुनाफे के आधार पर कंपनियों की परख करता है, लिहाजा उनका मुनाफा अगर 15 प्रतिशत बढ़ेगा, तो मार्केट रिटर्न भी 15 प्रतिशत होना चाहिए। इस तरह 10 वर्षों में 15 प्रतिशत की सालाना चक्रवृद्धि दर (CAGR) को ध्यान में रखें तो मामला चार गुने पर पहुंच जाता है। लिहाजा 50,000 पर मौजूद सेंसेक्स को चार गुना होकर 10 वर्षों में 2 लाख के स्तर पहुंच जाना चाहिए।

इस बार के बजट ने यह तस्वीर बनाए रखी है। अब सवाल आता है निवेशकों को इस बजट को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए? मेरा दांव बैंकिंग पर है, खासतौर से प्राइवेट बैंकों पर। अच्छी इकनॉमिक ग्रोथ इस सेक्टर के लिए डबल पॉजिटिव है। यानी कर्ज की मांग बढ़ेगी और क्रेडिट कॉस्ट भी कम होगी। इससे बैंकों का मुनाफा बढ़ेगा। इस बार के बजट में पीएम आवास योजना यानी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 66 प्रतिशत ज्यादा आवंटन किया गया है। यह सीमेंट सेक्टर के लिए अच्छी बात है। हालांकि सीमेंट सेक्टर में उत्पादन क्षमता काफी है, लिहाजा हो सकता है कि डिमांड बढ़ने का उतना असर न दिखे। सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात की है। कैपिटल गुड्स सेक्टर पर इसका निश्चित रूप से अच्छा असर होगा। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है कि कम रहे क्योंकि सप्लाई साइड इंफ्लेशन अपना असर दिखाएगी। इस तरह देखें तो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर को छोड़कर निवेश के लिहाज से चुनिंदा स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि किसी पूरे सेक्टर पर दांव लगाया जाए। कुलमिलाकर भारत का अतीत शानदार रहा है और इसका भविष्य भी शानदार रहेगा।

17 वर्ष बाद नक्सलियों के कब्जे से मुक्त हुआ ये इलाका

अब एशिया का बड़ा 'इमली' बाजार लेगा नई करवट

एनटीवी न्यूज

व्यापार रूट को दोबारा से शुरू कराने के लिए सीआरपीएफ की 165वीं बटालियन ने आईजी (ऑपरेशन) छत्तीसगढ़, डीआईजी (ऑपरेशन) सुकमा और एसपी व एएसपी सुकमा के साथ मिलकर नक्सलियों के खिलाफ रणनीति तैयार की, जो सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती थी...

नई दिल्ली। केंद्रीय सुरक्षा बल 'सीआरपीएफ' की 165वीं बटालियन ने छत्तीसगढ़ पुलिस को साथ लेकर एक ऐसा मुश्किल कार्य, संभव कर दिखाया है जिसका इंतजार 2006 से हो रहा था। सफलता की इस दहलीज तक पहुंचने के लिए सीआरपीएफ को कई बड़े जोखिमों से गुजरना पड़ा है, नक्सलियों के अनेक हमलों को नाकाम किया गया। 17 वर्ष के दौरान नक्सलियों के खिलाफ सैंकड़ों छोटे-बड़े ऑपरेशन किए गए। 2006 से पहले इमली मार्केट को लेकर जिस क्षेत्र की एशिया में तूती बोलती थी, नक्सलियों ने उसे बंद कर दिया था। सीआरपीएफ ने पुलिस के सहयोग से अब बीजापुर और दंतेवाड़ा को जोड़ने वाले व्यापार मार्ग को नक्सलियों के कब्जे से मुक्त करा दिया है। इतना ही नहीं, महज तीस दिन के भीतर वहां पर दो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (एफओबी) भी स्थापित कर दिए। ये एफओबी 'बेडरे' और 'कुंदर' में तैयार किए गए हैं। इसके चलते एशिया का सबसे बड़ा 'इमली' बाजार, अब एक नई करवट लेने की राह पर चल पड़ा है।

विकासात्मक गतिविधियों को मिलेगी रफ्तार

अधिकारियों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों के नक्सल प्रभावित इलाकों में सीआरपीएफ, स्थानीय पुलिस को साथ लेकर माओवादियों के ठिकानों पर दबिश दे रही है। सीआरपीएफ और राज्य पुलिस द्वारा, नक्सलियों को खदेड़ कर वहां फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (एफओबी) स्थापित किए जा रहे हैं। ये बेस न केवल रणनीतिक तौर पर, अपितु आसपास के क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों को भी पूरी तरह से खत्म करने में सहायक होंगे। इन कैंपों के जरिए स्थानीय निवासियों का भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है। लंबे समय तक नक्सलियों के प्रभाव को झेल चुके स्थानीय लोग, अब विकास का नया सवेरा देखना चाहते हैं। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में वहां बहुप्रतीक्षित विकासात्मक गतिविधियों को भी अब रफ्तार मिलने लगी है।

नक्सलियों ने सड़कें खोदी तो नष्ट किए बिजली उपकरण

सीआरपीएफ की 165वीं बटालियन ने लोकल पुलिस को साथ लेकर इमली बाजार के रूट को नक्सलियों के कब्जे से मुक्त कराने की रणनीति बनाई। 2006 के बाद जिला मुख्यालय बीजापुर और दंतेवाड़ा को जोड़ने वाला पुराना व्यापार मार्ग बाधित हो गया था। एशिया के सबसे बड़े इमली बाजार पर इसका व्यापक असर देखने को मिला। आंध्र प्रदेश, केरल व तमिलनाडु सहित कई क्षेत्रों की कनेक्टिविटी खत्म हो गई। माओवादियों ने एक रणनीति के तहत यहां की सड़कों को खोद दिया। उन्हें बीच से काट दिया। गहरी खाई खोदी गई। बिजली उपकरणों को नष्ट कर दिया गया। इस इलाके में नक्सलियों ने सरकारी योजनाओं का रास्ता रोक दिया। यहां तक कि कौन किसके साथ शादी करेगा, कुछ जगहों पर नक्सली इस हस्तक्षेप तक भी पहुंच गए थे। वे अपनी अघोषित सरकार चलाने लगे। सरकारी स्कीम के तहत कोई विकास कार्य जैसे तालाब खुदाई का कार्य होता तो उसमें से 20 फीसदी राशि ले लेते थे।

नक्सलियों पर पड़ी दोहरी मार, ठिकाना छोड़ कर भागे

व्यापार रूट को दोबारा से शुरू कराने के लिए सीआरपीएफ की 165वीं बटालियन ने आईजी (ऑपरेशन) छत्तीसगढ़, डीआईजी (ऑपरेशन) सुकमा और एसपी व एएसपी सुकमा के साथ मिलकर नक्सलियों के खिलाफ रणनीति तैयार की। 17 साल से जिस इलाके पर नक्सलियों का कब्जा था, उसे मुक्त कराना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। सीआरपीएफ ने इस चुनौती को स्वीकार किया। कई बड़े ऑपरेशनों के बाद कुंदर में एफओबी लगाया गया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने महज तीस दिन में ही 'बेडरे' में दूसरा एफओबी भी स्थापित कर दिया। सुरक्षा बलों ने सड़क को ठीक कराने और विकास की दूसरी योजनाएं शुरू कराने में भरपूर सहयोग दिया। यहां तक कि सीआरपीएफ जवानों ने अपनी सुरक्षा ड्यूटी से परे जाकर श्रमदान भी किया। सड़क पर मिट्टी डाली गई। वाहनों के लिए पक्का रास्ता तैयार किया। अब वहां नक्सलियों पर दोहरी मार पड़ी है। एक तो उनका प्रभाव खत्म कर दिया गया और दूसरा, जिस रास्ते से वे बीजापुर और दंतेवाड़ा के बीच खुली आवाजाही करते थे, अब वह बंद हो गई है।

विकास की राह पर रोजगार के नए अवसर

सुरक्षा बलों का स्थायी कैंप बनने से जगरगुंडा का इमली बाजार, अब विकास की नई राह पर चलना शुरू होगा। पुराना व्यापार मार्ग शुरू होने से मिर्च व महुआ के कारोबार में भी तेजी आएगी। सुरक्षा बलों के अधिकारियों का कहना है कि अगले पांच वर्ष में यह इलाका विकास की नई राह तय करेगा। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अब वह ट्रांजिट कॉरिडोर भी बंद हो जाएगा, जिसका उपयोग माओवादी पश्चिम बस्तर और दक्षिण बस्तर के बीच आवाजाही के लिए करते थे। ये एफओबी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जगरगुंडा-सिल्गर-बासागुड़ा एक्सिस पर बनाया गया है। यहां परिचालन शुरू होने से आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। माओवादी हिंसा को समाप्त करने, शांति और स्थिरता लाने के उद्देश्य से सीआरपीएफ ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में पुलिस बलों के साथ मिलकर सुदूर क्षेत्रों में लगातार नए एफओबी स्थापित किए हैं।

हादसा: केरल में गाड़ी में लगी आग, जिंदा जले पति-पत्नी; कर्नाटक में कार पर पलटा ट्रक, मां-बेटी की मौत

एनटीवी न्यूज

नई दिल्ली। केरल के कन्नूर में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। दरअसल यहां एक कार में अचानक आग लग गई और इस आग की चपेट में आकर कार में सवार दंपति जिंदा जल गए। घटना गुरुवार की है। हादसे में चार अन्य लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस के अनुसार, कार में छह लोग सवार थे। कन्नूर के जिला अस्पताल के पास अचानक उनकी कार में आग लग गई। आग लगते ही पीछे की सीट पर बैठे चारों लोग किसी तरह कार से उतरने में सफल हो गए और उन्होंने कार की अगली सीट पर बैठे पति-पत्नी को भी बचाने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। आग की चपेट में आकर पति-पत्नी जिंदा जल गए। हादसे में मारी गई महिला गर्भवती थी।

कार की टक्कर से दो की मौत

कर्नाटक के मंगलुरु में कार की टक्कर से दो लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना पादुपानमबुर इलाके के पास की है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना बुधवार देर रात में नेशनल हाइवे-66 पर हुई। जहां मध्य प्रदेश के इंदौर से एक लॉरी में सवार होकर मध्य प्रदेश निवासी बब्लू (23) अचल सिंह (30) और केरल के अनीश (42 वर्ष) केरल जा रहे थे। पादुपनामबुर इलाके में उनकी लॉरी में पंचर हो गया। जब लॉरी में सवार तीनों लोग टायर बदल रहे थे, तभी एक तेज गति से आ रही कार ने तीनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में बब्लू और अचल सिंह की मौत हो गई और अनीश गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बेंगलुरु में अलग-अलग हादसों में तीन की मौत

बेंगलुरु के आरएम नगर इलाके में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की डंबल मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोपी की पहचान 46 वर्षीय मोरिस के रूप में हुई है। दोनों की शादी 18 साल पहले हुई थी और दोनों के तीन बच्चे हैं।

वहीं बेंगलुरु की बानेरघट्टा रोड पर एक दर्दनाक हादसे में मां-बेटी की मौत हो गई। दरअसल एक कंक्रीट मिक्सचर ट्रक रास्ते पर जा रही कार पर पलट गया। जिससे कार सवार महिला गायत्री कुमार और उनकी बेटी समांथा कुमार की मौत हो गई। हादसे की वजह तेज गति मानी जा रही है। पुलिस ट्रक के ड्राइवर और मालिक की तलाश में जुटी है।

इनसाइड

याचिका में की गई मांग- नेताओं के एक से ज्यादा जगह से चुनाव लड़ने पर लगे रोक, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी प्रत्याशी को एक से ज्यादा सीटों पर लड़ने की इजाजत विधायी नीति से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए यह संसद का फैसला होगा कि इस राजनीतिक लोकतंत्र में यह विकल्प लोगों को मिलना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका को रद्द कर दिया, जिसमें नेताओं के किसी एक पद के लिए, एक से ज्यादा जगह से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला विधायिका से जुड़ा है। इसलिए इस पर फैसला संसद को ही करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी प्रत्याशी को एक से ज्यादा सीटों पर लड़ने की इजाजत विधायी नीति से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए यह संसद का फैसला होगा कि इस राजनीतिक लोकतंत्र में यह विकल्प लोगों को मिलना चाहिए या नहीं।

आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को मिलेगा घर, सरकार का बड़ा फैसला

हाल ही में मुख्यधारा में वापस लौटे एक माओवादी लिजेश ऊर्फ रामू के लिये घर बनाने का निर्णय लिया है। सरकार ने एर्णाकुलम जिले के कलेक्टर एवं पुलिस प्रमुख को रामू के घर के लिए उचित जमीन की तलाश करने का आदेश दिया है। केरल में माओवादियों को आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। पिनाराई विजयन सरकार की ओर से कहा गया है कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को पुनर्वास पैकेज के तहत घर दिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार ने हाल ही में मुख्यधारा में वापस लौटे एक माओवादी लिजेश ऊर्फ रामू के लिये घर बनाने का निर्णय लिया है। सरकार ने एर्णाकुलम जिले के कलेक्टर एवं पुलिस प्रमुख को रामू के घर के लिए उचित जमीन की तलाश करने का आदेश दिया है। बता दें, रामू ने कुछ समय पहले अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था।

गृह निर्माण में तेजी के लिए कमेटी गठित

इसके अलावा सरकार ने कलेक्टर, पुलिस प्रमुख और पंचायत उप निदेशक की एक समिति का भी गठन किया है। यह समिति गृह निर्माण में तेजी की जांच करेगी। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भूमि की पहचान करने तथा आवास का निर्माण करने के लिये अधिकतम 15 लाख रुपये की राशि आवंटित की जायेगी। 2018 में जारी एक आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने माओवादियों के लिए आत्मसमर्पण सह पुनर्वास पैकेज को लागू करने की अनुमति दी थी।

चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी और राजद की मान्यता रद्द करने की मांग करेगी विहिप

नई दिल्ली। विहिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल शीघ्र ही मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर इन दलों की मान्यता रद्द करने की मांग करेगा... विश्व हिंदू परिषद (विहिप) चुनाव आयोग से मिलकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की मान्यता समाप्त करने की मांग करेगा। संगठन ने कहा है कि इन दोनों दलों के प्रमुख नेता स्वामीप्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। चुनाव आयोग में एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दिए जाने के समय सभी पार्टियों को इस बात की शपथ देनी पड़ती है कि वह संविधान की पंथनिरपेक्षता की भावना का सम्मान करेगा। लेकिन इन दलों के नेताओं ने हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक पर अभद्र टिप्पणी कर अपने शपथ का उल्लंघन किया है। आरोप है कि यूपी में रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई गईं। विहिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल शीघ्र ही मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर इन दलों की मान्यता रद्द करने की मांग करेगा। उन्होंने इस संबंध में समय लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से विहिप 'रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951' की धारा 29ए का हवाला देते हुए चुनाव आयोग को बताएगी कि हर राजनैतिक दल को अपनी पार्टी के मेमोरेंडम के प्रावधानों में विश्वास रखते हुए पंथनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामीप्रसाद मौर्य के रामचरित मानस पर दिए गए बयानों, उसे प्रतिबंधित करने की मांग और उनके सहयोगियों के मानस के पवित्र पन्नों को जलाने से भारत के नागरिकों के बड़े वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर राजनीतिक लाभ के लिए घृणित तरीके से भड़काया गया। इसके तुरंत बाद मौर्य को पदोन्नत कर समाजवादी पार्टी का महामंत्री बनाया जाना भी यह स्पष्ट करता है कि इस कार्य में उन्हें अपनी पार्टी का समर्थन हासिल था। इसी प्रकार राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के शिक्षामंत्री डॉ चंद्रशेखर ने भी रामचरित मानस पर घृणित टिप्पणी और प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।

जनता के बीच जाने से पहले भाजपा सांसदों के साथ बैठक करेंगी वित्तमंत्री, समझाएंगी बजट की बारीकियां

एनटीवी संवाददाता

नई दिल्ली। वित्त मंत्री की यह बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने अपने सभी संसद सदस्यों से कहा है कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाएं और आम आदमी को बताएं कि इस बजट का क्या मतलब है। साथ ही उन्हें इसके फायदे भी गिनाएं।

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के भाजपा सांसदों के साथ एक बैठक करेंगी। इस दौरान वे बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी देंगी। इस बारे में सभी सांसदों को जानकारी दे दी गई है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी सांसदों से इस बैठक में शामिल होने के लिए तय समय और तय स्थान पर पहुंचने के लिए कहा गया है।

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को होने वाली ये ब्रीफिंग संसद पुस्तकालय भवन में बालयोगी सभागार में सुबह 9 बजे होगी। यह बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने अपने सभी संसद सदस्यों से कहा है कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाएं और आम आदमी को बताएं कि इस बजट का क्या मतलब है। साथ ही भाजपा का लक्ष्य आम जनता को इस बात का भी संदेश देना है, समाज के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए इसमें क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं।

इससे पहले बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। बजट में उन्होंने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का एलान किया। साथ ही वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर 5 और टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करके इस व्यवस्था में टैक्स स्ट्रक्चर को बदलने का भी प्रस्ताव दिया।

इसके अलावा, बजट में उन्होंने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का इरादा वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 फीसदी से नीचे लाने का है।

बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। बजट में उन्होंने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का एलान किया।

राज्य सरकार को आदेश- जिनका PFI से संबंध नहीं, संपत्तियों पर कुर्की हटाकर उन्हें रिहा करें

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि पीएफआई से वसूली के संबंध में पहचान की गई संपत्तियों के नाम, पते और सर्वेक्षण संख्या में कुछ गलतियां हुई हैं।

नई दिल्ली। केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जिन लोगों का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से कोई संबंध नहीं है और राज्य सरकार के राजस्व वसूली अधिकारियों द्वारा गलती से कुर्क की गई थी, उनकी संपत्तियों पर कुर्की हटाकर उन्हें रिहा किया जाए।

दरअसल, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि पीएफआई से वसूली के संबंध में पहचान की गई संपत्तियों के नाम, पते और सर्वेक्षण संख्या में कुछ गलतियां हुई हैं। इसके परिणामस्वरूप उन व्यक्तियों की कुछ संपत्तियों को गलत तरीके से कुर्क कर लिया गया जो संगठन से जुड़े नहीं थे। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत एक हलफनामे में यह जानकारी दी गई थी।

हाईकोर्ट ने पिछले साल 2 सितंबर को पीएफआई को आदेश दिया था कि वह 30 सितंबर को संगठन द्वारा आयोजित अवैध हड़ताल के दौरान भड़की हिंसा में केरल राज्य परिवहन निगम (केएसआरटीसी) को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दो सप्ताह के भीतर 5.20 करोड़ रुपये जमा कराए।

अपने हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा, आदेश (हाईकोर्ट के) के अनुपालन में आईजी द्वारा पहचान की गई संपत्तियों का विवरण, पंजीकरण कुर्की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भूमि राजस्व आयुक्त को भेज दिया गया था। चूंकि, ये सभी प्रक्रियाएं सीमित समय अवधि में शुरू की गई थीं, इसलिए पहचाने गए लोगों के नाम, पते, सर्वेक्षण संख्या आदि में कुछ समानता के कारण कुछ गलतियां हुईं। इसलिए इसके चलते उन व्यक्तियों की कुछ संपत्तियों को गलत तरीके से कुर्क कर लिया गया जो संगठन से जुड़े नहीं थे।

हलफनामे में कहा गया था, जब सरकार के संज्ञान में यह आया कि कुर्की में कुछ गलतियां हुई हैं, तो भू-राजस्व आयुक्त और राज्य पुलिस प्रमुख को इन संपत्तियों के संबंध में आगे की कार्यवाही को रोकने का निर्देश दिया गया था, जिन्हें गलती से पहचाना गया था।

18 जनवरी 2023 के आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पीएफआई से संबंधित 209 व्यक्तियों की संपत्तियों के संबंध में मांगी गई संपत्ति को कुर्क करने के लिए जिला कलेक्टरों को भेज दिया गया था। भू-राजस्व आयुक्त ने सूचित किया है कि उनमें से 177 संपत्तियों के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा तैयार की गई थी। कुर्की की कार्यवाही के संबंध में उठाए गए विवादों को देखते हुए शेष संपत्तियों का मूल्यांकन पूरा नहीं किया जा सका।

हाईकोर्ट ने इससे पहले सरकार को कार्यवाही पूरी करने के बाद 23 जनवरी या उससे पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इससे पहले भी, राज्य सरकार ने प्रतिबंधित पीएफआई और उसके सचिव से नुकसान की वसूली के अपने निर्देश का पालन न करने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी थी।